● वर्ष : 17 ● अंक : 155 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

दिल्ली से प्रकाशित गुरुवार 26 मार्च 2026 लोकतंत्र का स्तंभ

लोकसभा में चर्चा के बाद वित्त विधेयक, 2026 पारित, भारत तेजी से सुधारों के रास्ते पर

एजेंसी। नई दिल्ली

लोकसभा में चर्चा के बाद बुधवार को वित्त विधेयक, 2026 पारित कर दिया गया, जो वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्र सरकार के बजट प्रस्तावों को लागू करने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सदन में यह विधेयक विचार और पारित करने पेश किया था। वित्त विधेयक 2026 को लोकसभा ने 32 सरकारी संशोधन शामिल करने के बाद अपनी मंजूरी दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भारत तेजी से सुधारों के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में सुधार किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच, आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता के साथ किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है और लगातार आगे बढ़ रहा है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भारत में सुधार किसी दबाव में नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ किए जा रहे हैं और देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि

वित्त विधेयक 2026-27 पांच स्पष्ट सिद्धांतों पर आधारित है। सीतारमण ने कहा कि वित्त विधेयक में मध्यम वर्ग के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान हैं और उन दावों को खारिज कर दिया कि इससे केवल बड़े व्यवसायों को ही लाभ होता है। उन्होंने कहा कि पिछले छह साल की अवधि (2019-2024/25) में सेस का कुल इस्तेमाल उसकी कुल वसूली से ज्यादा रहा है। इस दौरान 15.14 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई, जबकि विभिन्न योजनाओं के तहत राज्यों को 15.97 लाख करोड़ रुपये भेजे गए। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि अगर पीएलआई योजना असरदार नहीं थी और उससे रोजगार पैदा नहीं हुए, तो तमिलनाडु ने अपने यहां पीएलआई आधारित निवेश को क्यों नहीं ठुकराया?" निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने जवाब में पीएलआई योजना पर तमिलनाडु के रुख पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाता है। अब वित्त विधेयक के जरिए इनकम टैक्स की दरों, ड्यूटी और दूसरे शुल्कों में किए गए बदलाव लागू होंगे, जिसका सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि लोग और कंपनियां सरकारी खजाने में कितना पैसा जमा करते हैं। उम्मीद है कि इन प्रावधानों से नागरिकों की खर्च करने लायक इनकम, बचत और निवेश पर मिलने वाले रिटर्न, और दूसरे उपायों पर असर पड़ेगा।

केंद्रीय बजट 2026-27 के मुख्य प्रस्ताव : केंद्रीय बजट 2026-27 के मुख्य प्रस्तावों में विकास को गति देने, रोज़गार के अवसर पैदा करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। ये बजट आधारभूत संरचना और निजी निवेश के लिए पूंजीगत खर्च से होने वाले विस्तार, 'युवाशक्ति' जैसी रोजगार और कौशल विकास की पहलों और क्रेडिट एवं इंसेंटिव के जरिए एमएसएमई को मदद देने पर जोर देता है। साथ ही विनिर्माण, उद्योग और कृषि को उत्पादन से जुड़ी योजनाओं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सिंचाई और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर से फ़ायदा होगा।

सरकार का करदाताओं को राहत देने, रोजगार और विकास पर जोरः वित्त मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार एमएसएमई, किसानों और सहकारी समितियों को सशक्त बना रही है। सीतारमण ने सदन को बताया कि रोजगार और विकास के केंद्र में हैं। उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि भारत में सुधार किसी दबाव में नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ किए जा रहे हैं और देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ रहा है। सरकार विश्वास के साथ सुधार कर रही है और टैक्स सिस्टम को आसान बनाया जा रहा है। ईमानदार करदाताओं को राहत, 17 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म और छोटे टैक्सपेयर्स के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस भरोसे पर आधारित टैक्स सिस्टम बनाने पर है, जिसके तहत ईमानदार करदाताओं के लिए परेशानियां कम की जा रही हैं। टैक्स प्रशासन को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

ईरान युद्ध का भारत पर असर? रुपया पस्त, जीडीपी सुस्त, महंगाई जबरदस्त

इजरायल- अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक साथ आक्रमण किया। ईरान पर इस युद्ध का जो असर पडना था, वह पड़ रहा है। अमेरिका और इजरायल के ऊपर युद्ध के जो परिणाम सामने आने थे, वह भी सामने आ रहे हैं। भारत इन दो पाटों के बीच में पिसता हुआ नजर आ रहा है। वैश्विक निवेश फर्म गोल्डमैन ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो रिपोर्ट जारी की है, वह चिंता बढ़ाने वाली है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से भारत की जीडीपी में कमी आने तथा महंगाई बढ़ने की चेतावनी दी गई है। भारतीय अर्थ व्यवस्था में सबसे बड़ी गड़बड़ी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने के कारण हो रही है। कच्चा तेल, गैस एवं जो भी सामान भारत आयात करता है, उसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमत बढ़ने का असर सभी चीजों पर पड़ेगा। जिसके कारण भारत में महंगाई बड़ी तेजी के साथ बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है।

भारत में खाद्य पदार्थ कच्चा तेल रासायनिक खाद तथा रोजाना उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि के आयात से भारत की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। भारत का आयात लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कच्चा तेल गैस इत्यादि का आयात पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ गया है। लगभग 85 फ़ीसदी कच्चा तेल और गैस आयात करनी पड़ रही है। आयातित वस्तुओं का अधिकांश भुगतान डॉलर मुद्रा में होने से भारत के ऊपर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय रुपए की गिरावट का असर डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट मे कहा गया है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया को ब्याजदरों में वृद्धि करनी पड़ेगी। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट चार फ़ीसदी तक आ सकती है।

भारत का राजस्व चालू खाते का घाटा दो फ़ीसदी और भी बढ़ सकता है। कच्चे तेल और गैस की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार मे कच्चे तेल की कीमतें न्यूनतम 105 डॉलर और अधिकतम 120 डॉलर प्रति बैरल की संभावना जताई गई है। इतना महंगा कच्चा तेल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में था। पिछले 10 वर्ष में कच्चे तेल का भाव 60 से 70 डॉलर प्रति बेरल से अधिक कभी नहीं रहा। भारत में महंगा तेल आयात होने से विदेशी मुद्रा का संकट बढ़ेगा। राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। इसके साथ-साथ महंगाई भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था में लगभग एक से डेढ़ फ़ीसदी गिरावट की बात रिपोर्ट में कही गई है। इसका बड़ा असर कृषि क्षेत्र में भी पडने जा रहा है। खाद को लेकर अभी मारामारी थी। अभी जो नया संकट सामने आया है, उसके बाद खाद का संकट भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगा। जिसका असर कृषि उत्पादन में पड़ना तय है। पिछले चार माह में भारत का निर्यात व्यापार घटा है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बदलाव हो रहे हैं उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

वैश्विक संकट के बीच कृषि मंत्री की बैठक,फार्मर आईडी' प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली। वैश्विक अस्थिरता के बीच केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने बुधवार को अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें किसानों के हितों की सुरक्षा और आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का फोकस इस बात पर है कि देश में खाद, बीज और अन्य कृषि संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे और किसानों को समय पर सभी सुविधाएं मिलती रहें। कृषि मंत्री ने उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 'फार्मर आईडी' प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करने पर विशेष जोर दिया, ताकि वितरण प्रणाली पारदर्शी बने और सही लाभ सही किसान तक पहुंचे। इस दिशा में जल्द ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ समन्वय बैठक भी की जाएगी। बैठक में साफ किया गया कि वैश्विक संकट का फायदा उठाकर खाद और बीज की कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यों को भी निर्देश दिए जाएंगे कि वे निगरानी बढ़ाएं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। कृषि मंत्री ने बीज उत्पादन से जुड़े पहलुओं की समीक्षा करते हुए बीज सुखाने के लिए आवश्यक गैस और एग्रो-केमिकल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

दिल्ली के वॉल्ड सिटी इलाके में अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 10 गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क

का पर्दाफाश करते हुए 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े नेटवर्क के जरिए अवैध हथियार भारत में सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक सब-मशीन गन समेत 21 अत्याधुनिक विदेशी हथियार और 200 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव कुमार यादव के अनुसार यह गिरोह पुरानी दिल्ली के वॉल्ड सिटी इलाके, खासकर जामा मस्जिद क्षेत्र से संचालित हो रहा था। संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाके का फायदा उठाकर आरोपी हथियारों की तस्करी और सप्लाई का काम कर रहे थे। जांच में सामने आया कि आरोपी एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप और वीओआईपी कॉल का इस्तेमाल करते थे और बार-बार सिम कार्ड एवं मोबाइल बदलते थे। भुगतान हवाला के जरिए किया जाता था। क्राइम ब्रांच की टीम ने इंस्पेक्टर मान सिंह, इंस्पेक्टर अरविंद सिंह और इंस्पेक्टर सुंदर गौतम के नेतृत्व में लगातार तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र की मदद से इस पूरे नेटवर्क को ट्रैक किया।

भारत 6जी तकनीक में करेगा वैश्विक नेतृत्वः सिंधिया

नई दिल्ली। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत 3जी के दौर में पीछे था, 4जी में विश्व के साथ चला, 5जी में आगे बढ़ा और अब 6जी में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि देश अब 6जी तकनीक में वैश्विक नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिंधिया ने बुधवार को लोकसभा में भाजपा सदस्य बिद्युत वरण महतो के एक सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में स्थापित भारत 6जी एलायंस का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इससे जुड़े संस्थानों की संख्या 14 से बढ़कर 85 तक पहुंच चुकी है। भारत 6जी के क्षेत्र में विश्व के लगभग 10 प्रतिशत पेटेंट में योगदान करेगा, जिनमें से

4000 पेटेंट पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। भारत का सर्वव्यापी संपर्क प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय मंचों 3जीपीपी और आईटीयू में स्वीकृत हो चुका है। उन्होंने कहा कि भारत 6जी एलायंस के अंतर्गत सात कार्य समूह सक्रिय हैं, जो स्पेक्ट्रम, उपकरण प्रौद्योगिकी, पुर्जे, हरित एवं स्थायित्व, जनसंपर्क और 6जी उपयोग मामलों जैसे क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं। इनकी प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है ताकि समयबद्ध और प्रभावी विकास सुनिश्चित हो सके। सिंधिया ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) के बारे में बताया कि इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में फरवरी 2024 में बनाया गया।

शहरों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन में ही मिलेगा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर

एजेंसी। नई दिल्ली

घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की बुकिंग समय-सीमा में बदलाव को लेकर सोशल मीडिया में फैल रही खबरों को केंद्र सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी के बुकिंग नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।शहरों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन में ही एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ समाचार रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट में एलपीजी रिफिल बुकिंग की संशोधित

समय-सीमा का दावा किया जा रहा है। इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) कनेक्शन के लिए 45 दिन, गैर-पीएमयूवाई सिंगल बॉटल कनेक्शन के लिए 25 दिन और गैर-पीएमयूवाई डबल बॉटल कनेक्शन के लिए 35 दिन बताया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि एलपीजी रीफिल बुकिंग की मौजूदा समयसीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी।

एलपीजी रिफिल बुकिंग समयसीमा में कोई बदलाव नहीं, लोग अफवाहों से बचें: केंद्र

नई दिल्ली। देश में एलपीजी रिफिल बुकिंग की समयसीमा को लेकर चल रही खबरों और सोशल मीडिया पोस्टों का केंद्र सरकार ने खंडन करते हुए गलत बताया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही लोगों से अफवाहों से बचने की भी अपील की है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) कनेक्शन के लिए 45 दिन, नॉन-पीएमयूवाई सिंगल सिलेंडर कनेक्शन के लिए 25 दिन और नॉन-पीएमयूवाई डबल सिलेंडर कनेक्शन के लिए 35 दिन की नई समयसीमा तय की गई है। मंत्रालय ने कहा यह जानकारी गलत है और मौजूदा व्यवस्था ही लागू है। वर्तमान नियमों के अनुसार एलपीजी रिफिल बुकिंग की समयसीमा शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन है। यह सभी प्रकार के कनेक्शन पर समान रूप से लागू होती है।

24 अकबर रोड और 5 रायसीना रोड के ऑफिस खाली करने कांग्रेस को नोटिस

नई दिल्ली। भारत के राजनीति के सबसे ऐतिहासिक पतों में से एक, 24 अकबर रोड, अब कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल सकता है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस को दिल्ली स्थित अपने दो प्रमुख कार्यालयों—24 अकबर रोड और 5 रायसीना रोड को खाली करने का बेदखली नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक पार्टी को ये दोनों संपत्तियां 28 मार्च तक खाली करनी होंगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इसकी पुष्टि की है कि नोटिस कुछ दिन पहले ही मिले थे, जिससे पार्टी के पास कानूनी और राजनीतिक बचाव के लिए बहुत कम समय बचा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय 24 अकबर रोड और एक और अहम जगह 5 रायसीना रोड के लिए बेदखली के नोटिस दिए गए हैं और खाली करने की आखिरी तारीख 28 मार्च तय की गई है। इससे कांग्रेस के अंदर बढ़ती बेचैनी है क्या वह इन दो राजनीतिक रूप से अहम संपत्तियों पर अपना कब्ज़ा बरकरार रख पाएगी। पार्टी अब अपने अगले कदमों पर विचार कर रही है, जिसमें अदालत जाना और सरकार से और समय मांगना शामिल है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस संपत्ति के आवंटन को फिर से व्यवस्थित करने के लिए थोड़े और समय का अनुरोध कर सकती है।

लिएंडर पेस ने की नितिन नबीन से मुलाकात, थाम सकते हैं बीजेपी का दामन

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जल्द ही टेनिस खिलाड़ी का साथ मिल सकता है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खबर है कि पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की है। खास बात है कि पेस राज्य में टीएमसी में करीब 5 साल पहले शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार शाम पेस और नबीन के बीच कोलकाता में बैठक हुई। उस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य भी मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि चर्चाएं चल रहीं हैं पेस जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। रिपोर्ट

के मुताबिक साल 2021 में गोवा में पेस ने टीएमसी ज्वाइन की थी। तब सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें अपना छोटा भाई बताया था। हालांकि, टीएमसी ने उस दौरान उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी और वह गोवा प्रदेश समिति के भी सदस्य नहीं बने थे। जनवरी 2022 में इस समिति की घोषणा हुई थी, जिसमें 69 सदस्य थे। मंगलवार को टीएमसी के नेता और पूर्व विधायक अर्घ्य रॉय प्रधान बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं जीसीपीए यानी ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन गुट से जुड़े और ग्रेटर कूच बिहार आंदोलन के अगुआ में से एक राजबंशी नेता बंशीबदन बर्मन भी यहां पार्टी के राज्य मुख्यालय में बीजेपीप में शामिल हो गए।

ईरान जंग का चुनाव पर असर, मिडिल ईस्ट में रहते हैं केरल के 20 लाख से ज्यादा लोग

एजेंसी। नई दिल्ली

अमेरिका और ईरान युद्ध का असर भारत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। खाड़ी देशों में भारतीयों के फंसे होने के कारण वोटर संख्या प्रभावित हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर केरल पर पड़ेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में केरल के 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑब्जर्वर्स का कहना है कि इसका असर मतदाताओं की संख्या पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि संख्या निर्णायक नहीं होगी, लेकिन कुछ इलाकों में इनका असर दिखेगा। वोट डालने के लिए यूएई, सऊदी अरब, कुवैत समेत कई

देशों से केरलवासी भारत आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मतदाताओं की संख्या का असर खासतौर से उत्तर केरल में नजर आएगा। इसके चलते मलप्पुरम, कोझिकोड और कासरगोड जिलों में असर देखा जा सकता है। साथ ही पलक्कड़ और थ्रिसूर कुछ प्रभावित हो सकते हैं। माना जा रहा है कि आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को इस वोटर का सबसे ज्यादा फायदा होता है। आईयूएमएल कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा है। पार्टी के महासचिव पीएमए सलाम का कहना हैं कि कई लोग वोटिंग के लिए वापस नहीं आ पाएंगे। हमारे केएमसीसी सदस्य खाड़ी देशों में अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन हालात सामान्य नहीं हुए तो मतदाताओं की संख्या कम रहेगी। सीपीआई से राज्यसभा सांसद संदोश कुमार पी कहते हैं कि उत्तर केरल में कुछ ही क्षेत्र हैं, जहां खाड़ी में रहने वाले मतदाताओं का संख्या ज्यादा है। आमतौर पर ये सीटें जीत के बड़े अंतर वाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष पुथूर रहमान बताते हैं कि हम यूएई से आमतौर पर 8 चार्टर्ड फ्लाइट्स की तैयारी करते हैं।

ईंधन संकट को लेकर देशभर में अफरा-तफरी का महौल, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें

एजेंसी। नई दिल्ली

देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैली अफवाहों ने आमजन में घबराहट पैदा कर दी है। नोएडा, हैदराबाद, नागपुर सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिलीं। लोग डिब्बों और बोतलों में भी ईंधन भरवाने के लिए उमड़ पड़े, जिससे कई स्थानों पर अस्थायी रूप से स्टॉक खत्म होने की स्थिति बन गई। अनेक जगहों पर तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई पंपों पर 'नो स्टॉक' के बोर्ड लगाने पड़े, हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह वास्तविक कमी नहीं, बल्कि अचानक बढ़ी मांग का परिणाम है। अधिकारियों के अनुसार, देश में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार

की कोई कमी नहीं है। यहां मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, देवास, मंदसौर, बुरहानपुर और झाबुआ में भी यही हाल देखने को मिला। उज्जैन में तो मंगलवार रात से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, जिसके चलते कई पंपों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा और स्थिति संभालने के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इस संबंध में प्रट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि अफवाह फैली है कि जल्द ही पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं, जिसके कारण लोग घबराहट में जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीद रहे हैं। हैदराबाद और नागपुर में भी सप्लाई सामान्य रहने के बावजूद लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। इसी बीच, एलपीजी गैस को लेकर भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अयोध्या, आगरा, उदयपुर और वडोदरा सहित कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई लोग सिलेंडर पाने के लिए घंटों, बल्कि रातभर इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय हालात, विशेषकर मिडिल ईस्ट तनाव के बावजूद भारत में ईंधन और एलपीजी की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक खरीदारी से बचें, ताकि सप्लाई व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने मां कालरात्रि से देश के सुख-समृद्धि की कामना की

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना कर

देशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर संस्कृत श्लोक साझा कर मां कालरात्रि की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि मां कालरात्रि का स्वरूप भय का नाश करने वाला है और वह अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। प्रधानमंत्री ने यह श्लोक साझा किया- "वामपादोल्लसल्लोहलताकण्टकभूषणा। वर्धन्मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी॥" इस का अर्थ है कि मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर और प्रभावशाली है। उनके बाएं पैर में चमकती हुई लोहे की जंजीरें और कांटों के समान आभूषण सुशोभित हैं। उनके सिर पर ऊंचा ध्वज विराजमान है और उनका वर्ण कृष्ण (अत्यंत काला) है। वह भय उत्पन्न करने वाली प्रतीत होती हैं, लेकिन अपने भक्तों के सभी भय और संकटों का नाश करने वाली हैं।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEU-TICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

ख़ास ख़बर

किसानों को 2013 से पहले अधिग्रहित जमीन पर भी मिलेगा बढ़ा मुआवजा

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण के मामले में किसानों को राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 2013 से पहले अधिग्रहित भूमि के लिए भी बढ़े हुए मुआवजा और ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने साफ किया कि सिर्फ वित्तीय बोझ का हवाला देकर किसानों का मुआवजा नहीं घटाया जा सकता है। दरअसल, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर 2013 से पहले विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि पर दिए बढ़े मुआवजे और ब्याज के पुराने फैसलों की समीक्षा की मांग की थी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कहना था कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के बाद ऐसे हजारों मामलों में मुआवजे का भारी वित्तीय बोझ सरकार पर आ गया है। ये करीब 29 हजार करोड़ रुपये का है। उच्चतम न्यायालय ने साफ किया कि केवल भूस्वामी ही बढ़े हुए ब्याज का दावा करने के हकदार होंगे, जिनके बढ़े हुए मुआवजे के मामले 28 मार्च 2015 तक किसी फोरम के समक्ष लंबित थे। इस तिथि तक ही लंबित रहे मामलों में कानून के मुताबिक बढ़ा हुआ मुआवजा और ब्याज दिया जाए।

सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को मंगलवार रात पेट में इंफेक्शन की शिकायत के बाद दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। बुधवार को अस्पताल द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, सोनिया गांधी को मंगलवार रात 10:22 बजे सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के चेयरमैन डॉ अजय स्वरूप ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टरों द्वारा उनकी विस्तृत जांच की जा रही है, जिसमें पेट और यूरिनरी ट्रैक में संभावित संक्रमण की जांच भी शामिल है। इलाज के तहत उन्हें एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं। अस्पताल की एक विशेषज्ञ टीम उनकी निगरानी कर रही है और आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है।

मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने सीएसआर में 200 करोड़ के योगदान की घोषणा की

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। ज्वेलरी समूह मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने आज वित्त वर्ष 2026–27 के लिए कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर के तहत 200 करोड़ के योगदान की घोषणा की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सीएसआर पहल के तहत देशभर की 33,000 छात्राओं के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति वितरण का शुभारंभ किया। मलाबार समूह के चेयरमैन एम.पी. अहमद, इंडिया ऑपरेशंस के प्रबंध निदेशक ओ. अशर, कार्यकारी निदेशक निशाद ए.के. और अब्दुल्ला इब्राहिम, केरल हाउस के रेजिडेंट कमिश्नर पुनीत कुमार (आईएएस), प्रथम के सीईओ रुक्मिणी बनर्जी और थानल के चेयरमैन डॉ. इदरीस सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि "मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द्वारा सीएसआर के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय देश की प्रगति को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा लोगों के सशक्तिकरण, विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण पर आधारित है, और शिक्षा के माध्यम से सार्थक परिवर्तन लाने के लिए कंपनी के प्रयास सराहनीय हैं। मलाबार समूह के चेयरमैन एम.पी. अहमद ने कहा कि "मानव संसाधन विकास राष्ट्रीय प्रगति की रीढ़ है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से प्रतिभा का विकास अत्यंत आवश्यक है। यह छात्रवृत्ति कार्यक्रम विद्यार्थियों को शैक्षणिक सफलता हासिल करने और देश के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाता है।" उन्होंने यह भी कहा कि समूह दीर्घकालिक और स्थायी सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं : सिरसा

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सदन को आश्वस्त किया कि राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, "मैं सारे सदन को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में एलपीजी के वितरण के संबंध में किसी भी तरीके की अफवाह को बढ़ावा न दिया जाए। डिपार्टमेंट पूरी मुस्तैदी से कालाबाजारी को रोकने और सप्लाई को सुचारू रखने के लिए काम कर रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पिछले 22-25 दिनों से स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है, कोई ओवरबुकिंग या कमी नहीं दिखी। रिहायशी और व्यावसायिक सिलेंडर केंद्र सरकार की नीति के तहत प्राथमिकता आधार पर उपलब्ध हो रहे हैं, जिसमें अस्पतालों सहित सभी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।सिरसा ने कहा, "त्योहार के लिए सिलेंडर की जरूरत है, और मैं सारे सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं, कहीं भी इस त्योहार के दौरान भी, एक भी दिन, एक भी घंटे के लिए, किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मंत्री ने आश्वस्त किया यदि कहीं कोई शिकायत आती है, तो उनका कार्यालय तत्काल कार्रवाई करेगा। दिल्ली सरकार लगातार निगरानी रख रही है तथा अफवाहों पर सख्ती बरत रही है।

डीयू के सीआईपीएस ने किया प्रधानमंत्री संग्रहालय के शैक्षिक भ्रमण का आयोजन

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज (सीआईपीएस) ने छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय के सहयोग से मंगलवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय (पीएमएस) का एक शैक्षिक भ्रमण आयोजित किया। सीआईपीएस के अध्यक्ष प्रो. रवि टेकचंदानी, निदेशक प्रो. रविंदर कुमार, संयुक्त निदेशक प्रो. ज्योति त्रेहन शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विभाग की संयुक्त डीन प्रो. संगीता गडरे, उप डीन डॉ. चंद्रप्रकाश, उप डीन डॉ. सुरेश गोहे, सीआईपीएस कार्यात्मक समिति के सदस्य और दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में अनाथ श्रेणी के तहत प्रवेश प्राप्त 34 विद्यार्थियों ने इस दौरे में सक्रिय रूप से भाग लिया। विद्यार्थियों ने भ्रमण के पश्चात कहा कि पीएमएस की प्रत्येक गैलरी का दौरा करना एक अत्यंत ज्ञानवर्धक अनुभव रहा। भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्रियों के गौरवशाली योगदान और चुनौतियों के इतिहास की एक अभिनव डिजिटल वर्णनात्मक प्रस्तुति यहां प्रस्तुत की गई है। पीएमएस के निदेशक ने स्वागत किया और हमारे प्रयासों की सराहना करते हुए सीआईपीएस के साथ भविष्य में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। ज्ञानवर्धक और अद्भुत शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय और प्रधानमंत्री संग्रहालय के प्रति आभार व्यक्त किया। सीआईपीएस विभाग के निदेशक प्रो. रविंदर कुमार ने कुलपति प्रो. योगेश सिंह को उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि सीआईपीएस विभाग की स्थापना उनकी पहल और दूरदृष्टि के फलस्वरूप हुई।

डीयू कुलपति ने किया स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने बुधवार को रामजस कॉलेज के सामने, सामाजिक विज्ञान संकाय परिसर में नए बने प्रेरणा भवन का उद्घाटन डूसू पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया। यह भवन स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर होगा जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) कार्यालय भी बनाया गया है। औपचारिक उद्घाटन के बाद कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने पूरे भवन का अवलोकन किया और कहा कि यह प्रेरणा भवन विद्यार्थियों के लिए प्रेरक होगा। उन्होंने बताया कि यह भवन विभिन्न छात्र केन्द्रित गतिविधियों का केंद्र रहेगा। इस अवसर पर कुलपति ने डूसू पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी की और स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर के संचालन को लेकर सुझाव भी दिये। कुलपति ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस प्रेरणा भवन के भूतल पर 50 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक कैफेटेरिया बनाया गया है और उसके साथ ही एक यूटिलिटी शॉप बनाई गई है। कैफेटेरिया में स्टोर रूम और किचन की अलग से व्यवस्था की गई है। भवन के बेसमेंट में जिम और गेम जोन बनाया गया है। इमारत के प्रथम तल पर 120 लोगों की बैठने की क्षमता का एक सेमिनार हाल बनाया गया है। द्वितीय तल पर एक मीटिंग रूम और डूसू अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व संयुक्त सचिव के लिए अलग-अलग कार्यालय बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रेरणा भवन में प्रत्येक तल पर अलग-अलग महिला एवं पुरुष शौचालयों की व्यवस्था भी की गई है। भवन के तृतीय तल पर एक आधुनिक सुविधा संपन्न लाइब्रेरी एवं एक रीडिंग हॉल की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर कुलपति प्रो. योगेश सिंह के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी, डीयू के वित्त अधिकारी गिरीश रंजन, चीफ इंजीनियर अशोक सैनी, डीन स्टूडेंट्स वेल्फेयर प्रो. रंजन कुमार त्रिपाठी, डूसू के स्टाफ एडवाइजर प्रो. सुरेंद्र कुमार और डूसू अध्यक्ष आर्यन मान व उपाध्यक्ष राहुल झांसला यादव सहित सभी डूसू पदाधिकारी एवं अनेकों शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से की शिष्टाचार भेंट

मुख्यमंत्री - प्रधानमंत्री के दूरदर्शी विजन और नेतृत्व में राजस्थान छू रहा नई ऊंचाइयां

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री को नवरात्र पर्व की शुभकामना एवं बधाई देकर राजस्थान के शिल्पकार द्वारा चंदन की लकड़ी से निर्मित मां दुर्गा की मूर्ति भेंट की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस मुलाकात में प्रधानमंत्री श्री मोदी से विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की योजनाओं और नीतियों के सफल क्रियान्वयन से आमजन लाभांवित हो रहे हैं। वहीं, राजस्थान विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां को छू रहा है।

नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित 11 दिवसीय राजस्थान उत्सव का हुआ भव्य समापन

» राजीविका और रूडा के हस्तशिल्प स्टॉल्स पर हुई 80 लाख से ज्यादा की रिकार्ड बिक्री

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध उत्सवों में एक राजस्थान उत्सव-2026 प्रदेश की अमिट और अनुपम छाप छोड़कर बुधवार को समाप्त हो गया। बीकानेर हाउस परिसर में आयोजित इस 11 दिवसीय राजस्थान उत्सव में जहां एक ओर राजस्थान की कला और संस्कृति का संगम दिखा वहीं दूसरी ओर राजस्थान व्यंजनों के स्वादों ने सबकी सराहना समेटी। राज्य की अतिरिक्त आवासीय आयुक्त श्रीमती अंजू ओमप्रकाश ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुभारंभ किया गया राजस्थान उत्सव अपनी पूरी अवधि में राजधानी वासियों के आकर्षण का केन्द्र बना रहा। पूरे उत्सव में महिलाओं, पुरूषों के साथ-साथ हर उम्र के बच्चों के मनोरंजन का विशेष ध्यान रखा गया। बीकानेर हाउस का प्रांगण मेले की आभा से आलोकित रहा और पूरा परिसर 'राजस्थानमय' नजर आया। 11 दिवसीय इस उत्सव ने न केवल सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया, बल्कि राज्य के कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों के लिए आर्थिक अवसर भी सृजित किए।

गणगौर की सवारी– अंजू ओमप्रकाश ने बताया कि राजस्थान के मशहूर गणगौर उत्सव को देखते हुए बीकानेर हाउस में 200 महिलाओं के समूह ने राजस्थानी परिधानों में गणगौर की सवारी निकाली जिसकों देखने के लिए सैकड़ो की संख्या में दर्शक एकत्रित हुए। राजीविका और रूडा और सरस के स्टॉल्स बने आकर्षण का केंद्र।

विकास की दौड़ के बीच वन्यजीव सुरक्षा पर कार्रवाई आवश्यकः हर्ष वर्धन श्रृंगला

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य हर्ष वर्धन श्रृंगला ने बुधवार को संसद में मानव और वन्यजीवों के सह-अस्तित्व के लिए एक व्यापक और संवेदनशील दृष्टिकोण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास में उसके नागरिकों और उसकी प्राकृतिक विरासत, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ऐसा देश होने के नाते जो वैश्विक जैव विविधता प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है और 'ग्लोबल बिग कैट अलायंस' की मेजबानी कर रहा है, भारत की यह जिम्मेदारी है कि वह यह साबित करे कि विकास और पारिस्थितिक संतुलन साथ-साथ चल सकते हैं। श्रृंगला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कथन को याद किया, जिसमें उन्होंने संरक्षण को राष्ट्र की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बताया है। उन्होंने कहा कि असम में हाल ही में एक ट्रेन की चपेट में आने से सात हाथियों की मौत की घटना एक कड़वी याद दिलाती है कि विकास की कीमत जान नहीं हो सकती और उन्होंने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक संवेदनशील योजना बनाने का आह्वान किया। उन्होंने 'काजीरंगा मॉडल' की ओर इशारा किया जहां बुनियादी ढांचे के विकास को जारी रखते हुए वन्यजीवों की आवाजाही को बहाल करने के लिए ऊंचे गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने संरक्षण के क्षेत्र में भारत द्वारा प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग को भी रेखांकित किया; जिसमें गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट-टैगिंग, हाथियों की पहली डीएनए- आधारित जनगणना और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घड़ियाल तथा स्लॉथ बीयर जैसी प्रजातियों के लिए विशेष संरक्षण प्रयास और साथ ही चीता पुनर्स्थापन (ट्रांसलोकेशन) की पहलें शामिल हैं। श्रृंगला ने संवेदनशील गलियारों में 'वन्यजीव-संवेदनशील विशेष क्षेत्र' बनाने, ग्राम पंचायतों और जैव विविधता निकायों को शामिल करते हुए 'स्थानीय संरक्षण परिषदों' का गठन करने और हाथियों के रास्तों से गुजरने वाली ट्रेनों में (विशेषकर उत्तरी बंगाल और असम में) एआई-सक्षम घुसपैठ-पहचान प्रणालियों को तैनात करने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि अब भारत को विकास का एक ऐसा मॉडल बनाकर वैश्विक स्तर पर एक मिसाल कायम करनी चाहिए, जहां मानवता और प्रकृति दोनों साथ-साथ फलें-फूलें और जिसकी नींव करुणा तथा नवाचार, दोनों पर टिकी हो।

सरकार से शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, डिजिटल संप्रभुता पर ठोस नीतिगत कदम उठाने की मांग

लोकतंत्र की शान

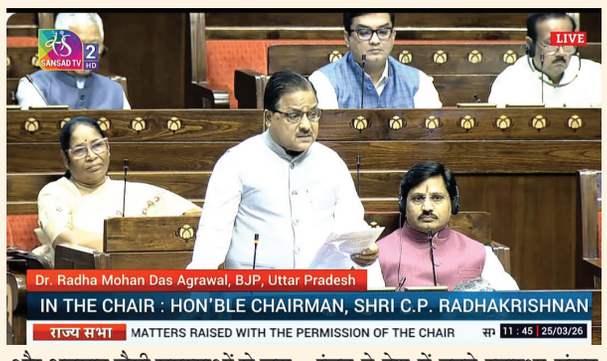

नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान शिक्षा व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण संबंधी जानकारी और डिजिटल संप्रभुता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सदस्यों ने सरकार से इन मुद्दों पर ठोस नीतिगत कदम उठाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि आज की प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली में अंकों की होड़ के कारण पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। परिवार, स्कूल और समाज के दबाव के चलते बच्चे अत्यधिक तनाव में हैं और कोचिंग पर निर्भर हो रहे हैं। उन्होंने एक अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि देश में बड़ी संख्या में बच्चे तनाव, चिंता, भावनात्मक असंतुलन और अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव पर चिंता जताते हुए प्रत्येक 100 छात्रों पर एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की नियुक्ति की मांग की। साथ ही शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। कांग्रेस सदस्य रंजीता रंजन ने देश में बढ़ते स्वास्थ्य संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत में मधुमेह और मोटापे के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट और सरल पोषण संबंधी जानकारी के अभाव को गंभीर समस्या बताते हुए उन्होंने पैकेट के सामने रंग-आधारित चेतावनी प्रणाली लागू करने की मांग की। इससे खाद्य कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव होगा। कांग्रेस सदस्य नीरज डांगी ने डिजिटल संप्रभुता का मुद्दा उठाते हुए भारत में स्वदेशी सर्च इंजन विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि चीन, रूस, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, चेक रिपब्लिक और वियतनाम समेत कई देशों का अपना स्वदेशी सर्च इंजन है। इन देशों ने स्वदेशी सर्च इंजन को विकसित कर अपनी डिजिटल संप्रभुता को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत में स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि हमारे 140 करोड़ लोगों का अधिकांश डेटा विदेशी सर्च इंजन के माध्यम से संग्रहित और विश्लेषित होता है। ये गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

'वंदे मातरम' को लेकर केंद्र के दिशा-निर्देश को चुनौती देने संबंधी याचिका खारिज

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाने संबंधी केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देश में इसका पालन नहीं करने पर कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है, ऐसे में ये याचिका प्री-मैच्योर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक प्रोटोकॉल है वंदे मातरम गाना बाध्यकारी नहीं है। यह याचिका मुहम्मद सैयद नूरी ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उठकर वंदे मातरम गाने से मना करता है, तो उसे भी इस दिशानिर्देश की आड़ में वंदे मातरम गाने पर मजबूर किया जा सकता है। तब जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने पूछा कि क्या इस दिशा-निर्देश में ऐसा कोई प्रावधान है, जो दंडात्मक हो। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या कभी याचिकाकर्ता को वंदे मातरम गाने के लिए बाध्य किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ता स्कूल चलाते हैं, हमें नहीं मालूम कि वो मान्यता प्राप्त है या नहीं।

केंद्र ने क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' 2.0 को मंजूरी दी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' के संशोधित संस्करण (उड़ान 2.0) को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए 28,840 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक 10 वर्षों के लिए लागू होगी, जिसका लक्ष्य 100 नए हवाई अड्डों/हेलीपोर्ट को विकसित करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 28,840 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ संशोधित क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना 'उड़ान' 2.0 को मंजूरी प्रदान की गयी। वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक दस साल की अवधि के लिए 'क्षेत्रीय संपर्क योजना–संशोधित 'उड़ान' के शुभारंभ और कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए भारत सरकार के बजटीय सहयोग से कुल 28,840 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। संशोधित 'उड़ान' योजना के तहत, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा अप्रयुक्त हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डों को विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कुल 12,159 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना में 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कुल 3,661 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके अलावा बाजार के लंबे समय तक विकास की आवश्यकता को देखते हुए एयरलाइन ऑपरेटरों को वीजीएफ सहायता देने का प्रस्ताव है, जिसकी राशि 10,043 करोड़ रुपये होगी।

केरल में बड़े बैंक लेन-देन पर आयकर विभाग की सख्त निगरानी, डॉ. भार्गव मल्लप्पा से हुई पूछताछ

आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद डॉ. मल्लप्पा को मिली राहत

लोकतंत्र की शान

केरल। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद, जिसे 15 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया था, राज्य में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के साथ ही वित्तीय लेन-देन पर निगरानी और सख्त कर दी गई है। इसी क्रम में केरल से एक मामला सामने आया है, जहां आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद किए गए एक बड़े नकद निकासी लेन-देन ने चुनाव अधिकारियों और आयकर विभाग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 16 मार्च को, आचार संहिता लागू होने के अगले ही दिन, कृष्णागिरी जिले के निवासी डॉ. भार्गव मल्लप्पा ने अपनी पत्नी रागिन मारिया के एक्सिस बैंक खाते से 12 लाख रुपये की नकद निकासी की। इसी दिन लगभग 7.50 लाख रुपये मूल्य का सोना भी खरीदा गया। इन लेन-देन को चुनाव आयोग के अधिकारियों ने संदिग्ध मानते हुए जांच के दायरे में लिया, क्योंकि चुनावी अवधि के दौरान नकदी के असामान्य प्रवाह पर विशेष नजर रखी जाती है, ताकि किसी भी प्रकार के चुनावी प्रभाव को रोका जा सके। इसके बाद आयकर विभाग ने डॉ. मल्लप्पा से संपर्क कर निकासी पर्ची और खरीद के बिल सहित संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। मौजूदा नियमों के अनुसार, आचार संहिता के दौरान व्यक्ति अपने बैंक खाते से किसी भी राशि की निकासी कर सकता है, लेकिन 10 लाख रुपये या उससे अधिक की निकासी की सूचना स्वतः आयकर विभाग को दी जाती है। वहीं, 50,000 रुपये से अधिक नकद राशि बिना वैध दस्तावेज के साथ ले जाने पर चुनाव निगरानी दल द्वारा उसे जब्त भी किया जा सकता है। डॉ. मल्लप्पा, जो एक प्रतिष्ठित सोशल प्रेन्योर के रूप में जाने जाते हैं, ने स्पष्ट किया कि यह निकासी और खरीदारी उनके परिवार में होने वाले बहन के विवाह की तैयारियों के लिए की गई थी। आवश्यक दस्तावेज और बिल प्रस्तुत करने के बाद मामले का समाधान हो गया और आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में डॉ. मल्लप्पा ने कहा कि यह लेन-देन पूरी तरह पारिवारिक जरूरत के तहत किया गया था और उन्होंने सभी नियमों का पालन किया है। उन्होंने यह भी बताया कि वे पहले भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सहयोग करते रहे हैं और आगे भी सभी नियमों का पालन करते रहेंगे। डॉ. मल्लप्पा एक जिम्मेदार नागरिक और नियमित करदाता हैं, जिनके खिलाफ पहले किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है। उनके द्वारा समय पर और पारदर्शी तरीके से दस्तावेज उपलब्ध कराने के चलते जांच प्रक्रिया बिना किसी विलंब के पूरी हो सकी। यह घटना दर्शाती है कि आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग और आयकर विभाग किस तरह से कड़ी निगरानी बनाए रखते हैं, जहां सामान्य और वैध वित्तीय गतिविधियां भी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जांच के दायरे में लाई जाती हैं।

संक्षिप्त समाचार

योगी सरकार का बड़ा फैसला रामनवमी पर दो दिन का अवकाश

» 26 के साथ अब 27 मार्च को भी रहेगी छुट्टी

» प्रदेशभर के मंदिरों में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला

लोकतंत्र की शान : लखनऊ : रामनवमी के अवसर पर प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अवकाश को एक दिन और बढ़ा दिया है। अब 26 मार्च के साथ-साथ 27 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला प्रदेशभर के मंदिरों में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। लगातार दो दिन की छुट्टी से श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना और दर्शन में सुविधा मिलेगी। साथ ही व्यवस्थाओं को भी बेहतर ढंग से संभाला जा सकेगा। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर रामनवमी के दौरान हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी अयोध्या समेत प्रदेशभर में मंदिरों में भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए अवकाश बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

अतिरिक्त अवकाश से यातायात को सुव्यवस्थित करने में मिलेगी मदद-प्रदेश सरकार के इस कदम को आस्था के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। अतिरिक्त अवकाश से यातायात, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने में भी मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार पहले ही 26 मार्च को अवकाश घोषित कर चुकी थी, जिसे अब बढ़ाकर 27 मार्च तक कर दिया गया है।

मुखिया गुर्जर ने भाजपा विधायक व कमाल अख्तर पर साधा निशाना

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा: हसनपुर। सपा के पूर्व प्रत्याशी मुखिया गुर्जर ने भाजपा सरकार एवं स्थानीय विधायक तथा कमाल अख्तर पर निशाना साधते हुए कमाल अख्तर को हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ाये जाने की मांग की है। बुधवार को नगर के एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी रहे मुखिया गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार में लूट हत्या बलात्कार से ही प्रदेश की पहचान हो रही है। उनके ऊपर तथा सपा के 30 /35 कार्यकर्ताओं पर प्रशासन ने पांच फर्जी मुकदमे कराये गये हैं। उन्होंने कमाल अख्तर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन मुकदमों में अपने लोगों की भी भूमिका रही है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से उनका रिश्ता रहा है। यहां की जनता ने उन्हें करीब 1 लाख वोट दिये थे। जिसका वह अहसान नहीं उतार सकते। उन्होंने कहा कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा के वरिष्ठ नेता कमाल अख्तर को 2027 में चुनाव लड़ाया जाये। कमाल अख्तर में 50 से 60 हजार वोटो से जीतने की क्षमता है। इस बार प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में सपा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वही कमाल अख्तर ने पलट बार करते हुए मुखिया गुर्जर का हसनपुर विधानसभा से उन्हें चुनाव लड़ने का राष्ट्रीय अध्यक्ष से की गई से सिफारिश को लेकर आभार व्यक्त करते हुए कहां की जब मुखिया गुर्जर पर मुकदमे लगे थे उसमें सपा कार्यकर्ताओं जिसमें गरीब लोग हैं उन मुकदमों की पेरवी के लिए मुखिया गुर्जर को उनका खर्चा बहन करना चाहिए था क्योंकि मुकदमे मुखिया गुर्जर की वजह से लगे हैं और उन्होंने कहा कि रही चुनाव लड़ने की बात तो हसनपुर की जनता के दिल में वह बास करते हैं, इस अवसर पर राजपाल चौहान, राशिद चौधरी, प्रदीप यादव, धर्मपाल यादव, आलम बंजारा, दीपक गुर्जर मौजूद रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेसन महमूदाबाद में जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

लोक तंत्र की शान ,देवेंद्र सिंह : महमूदाबाद- सीतापुर/ उ0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन में व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर '' आशीष जैन'' की अध्यक्षता में दिनांक- 25.03.2026 को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय भान, द्वारा सीताग्रुप ऑफ एजेकेशन महमूदाबाद सीतापुर में एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम युवाओं

के मस्तिष्क में हमेशा नये विचार जन्म लेते हैं। अपने नए विचारों को युवा जब देश और समाज की सेवा में लगाता है तो इससे प्रगति बढ़ती है। युवा ही समाज और देश की असली ताकत है। पढ़ाई के साथ-साथ समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों को उनके अधिकारों कर्तव्यों की जानकारी उपलब्ध करवाकर न्याय दिलाने में सहायता करना भी हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप सभी समाज का दर्पण है। जब आप शिक्षित होंगे तभी समाज भी शिक्षित होगा। सीता ग्रुप ऑफ एजूकेशन के शास्त्री सभागार में विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में आए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के अध्यक्ष आशीष जैन ने उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि जीवन में लक्ष्य का निर्धारण बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को जीवन में सदैव बड़े लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उनकी प्राप्ति हेतु निरंतर कठिन परिश्रम करना चाहिए। विधिक सेवा प्राधिकरण सभी के लिये निशुल्क व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिये हमेशा तत्पर है। मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट अतिथियों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजयभान, सिविल जज जूनियर डिवीजन रोहित पुरी, वरिष्ट लिपिक अशोक राणा, प्राविधिक स्वयंसेवक आदित्य वर्मा, भानु मिश्र, उमाशंकर, राजेंद्र वर्मा का स्वागत संस्था के चेयरमैन आरके वाजपेयी, कार्यालय प्रमुख राकेश शुक्ल, व्यवस्था प्रमुख शिवसेवक मिश्र ने बैज अलंकरण, माल्यार्पण, अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंटकर किया। कार्यक्रम का संचालन विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता भूपेंद्र दीक्षित व आभार प्रदर्शन कॉलेज के चेयरमैन आरके वाजपेयी द्वारा किया गया !

गैस न मिलने पर उपभोक्ताओं ने बाईपास मार्ग किया जाम,पुलिस ने खुलवाया

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः बुधवार को नगर की पुरानी गैस एजेंसी पर सिलेंडर न मिलने से परेशान उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया और संभाल बायपास मार्ग पर जाम लगा दिया सूचना मिलने पर हसनपुर पुलिस बल भी मौका पर पहुंचे और उपभोक्ता को समझो जान खुलवाया उपभोक्ताओं का आरोप है कि हसनपुर इंडियन गैस एजेंसी द्वारा उन्हें कई दिनों से गैस सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं पर लगातार एजेंसी पर तथा गोदाम पर लाइन में खड़े हो रहे हैं लेकिन एजेंसी मालिक नई-नई बनी बनाकर उन्हें डाल रहे हैं उपभोक्ताओं ने गैस की कालाबाजारी कभी मालिकों पर आरोप लगाया कई उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें गैस सिलेंडर मिले भी नहीं है लेकिन गैस मिलने का मैसेज भेज दिया गया है बुधवार को गैस न मिलने पाने के कारण उपभोक्ताओं का धैर्य जवाब दे गया गुस्सा आए उपभोक्ताओं ने संभाल बायपास मार्ग पर जाम लगा दिया सूचना मिलते ही कोतवाल राजेश कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने उपभोक्ताओं को समझा कर जाम खुलवाया, जाम खुलने के बाद भी उपभोक्ताओं का गैस एजेंसी स्वामी से नवजोत व हंगामा जारी रहा सूचना पाकर भारतीय किसान यूनियन सी आर अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भाटी भी मौके पर पहुंच गए उन्होंने मांग की कि जिन उपभोक्ताओं की गैस बुक हो चुकी है एजेंसी स्वामी उनके घरों तक सीलेंडर पहुंचाएं इस दौरान घंटो हंगामे की स्थिति बनी रही, दिग्विजय भाटी ने उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर जाम लगा रहे लोगों को समझा कर जाम खुलवाने में मदद की तथा जाम खुलवाकर उच्च अधिकारियों से कहा कि गैस उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान कराया जिसमें नायब तहसीलदार हसनपुर,सप्लाई इंस्पेक्टर हसनपुर,SHO हसनपुर व अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे तथा गैस एजेंसियों के मालिकों को बुलाकर समझाया व समस्या का समाधान कराया। इस मौके पर डॉ दिग्विजय भाटी, सोनू गुर्जर ,अरविंद जाटव, नन्हे यादव, रूम सिंह खड़कवंशी, नदीम चौधरी, यासीन कुरेशी, तयूब सैफी, दीपक गुर्जर, कुलदीप भारती, सीमा यादव, जितेंद्र सिंह, जगवती, आसमा, सुरेश, जगदीश आदि लोग मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने किए मां पाटेश्वरी के दर्शन

लोक तंत्र की शान

लखनऊ/बलरामपुर : गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि में बुधवार को तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन, पूजन-अर्चन किया। मां की आरती उतारी और सुखी, स्वस्थ व समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। सीएम योगी बुधवार को बहराइच में आयोजित कार्यक्रम के उपरांत बलरामपुर पहुंचे। यहां दर्शन-पूजन के बाद उन्होंने गोरखपुर के लिए प्रस्थान किया। सीएम ने मंदिर में आये श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। सीएम ने रामनवमी के अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा व स्वच्छता की समुचित व्यवस्था का भी निर्देश दिया।

शिवसेना की बैठक में केंद्र सरकार पर जमकर साधा गया निशाना

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः बुधवार को शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की एक महत्वपूर्ण बैठक शिवसेना के नगर अध्यक्ष विकास यादव के यादव सराय स्थित आवास पर आयोजित की गई जिसमें गैस की समस्या को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया बैठक को सम्बोधित करते हुए नगर प्रमुख विकास यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर लोगों को लाइन में खड़ा करने को मजबूर कर दिया है, उन्होंने कहा कि नोटबंदी के समय भी लोगों को लाइनों में लगा पड़ा था अपने रुपए को बैंक में जमा करने और निकालने के लिए घंटे लाइनों में लगा पड़ा था आज आत्मनिर्भर भारत की पोल ईरान इराक अमेरिका युद्ध के चलते खुल गई है उन्होंने कहा कि एक और हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं वहीं दूसरी ओर गैस तेल डीजल के लिए दूसरे देश पर निर्भर हैं और अपने देश में इतना पर्याप्त स्टॉक भी नहीं है कि दो-तीन महीने तक का काम चल जाए यदि युद्ध लंबा होता है तो भारत को किसी का मुंह ना देखना पड़े ऐसी व्यवस्था करने में प्रधानमंत्री /केंद्र सरकार फेल हो रही है, उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी आज गैस के संकट को झेल रही है क्योंकि ज्यादातर लोग घरेलू गैस पर ही निर्भर हैं, उन्होंने कहा कि हसनपुर नगर की पुरानी गैस एजेंसी पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गैस बुक करने के 15 दिन बाद भी लोगों को होम डिलीवरी नहीं मिल पा रही है तथा गोदाम पर भी तीन-चार दिन तक लाइनों में लगातार खड़े होकर लोग खाली हाथ वापस लौट रहे हैं यह केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के फेल होने का कारण है, अधिकारियों को हसनपुर गैस एजेंसी की ओर ध्यान देना चाहिए और हसनपुर गैस एजेंसी को निरस्त कर अन्य गैस एजेंसी में सम्मिलित कर देना चाहिए, बैठक की अध्यक्षता पूर्व नगर प्रमुख राजकुमार सागर ने की संचालन पूर्व नगर कोषाध्यक्ष रमेश यादव ने किया, बैठक में मुख्य रूप से राजू प्रजापति, अर्जुन यादव, दीपांशु, हेमंत, भूरे यादव उर्फ छोटू, छुट्टन यादव, दयाशंकर यादव, सतवीर प्रजापति, राजपाल प्रजापति आदि मौजूद रहे ।

मिशन शक्ति 5.0: महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता अभियान तेज

लोक तंत्र की शान

सम्भल/सिरसी थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र में चला विशेष अभियान जनपद संभल में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत थाना हजरतनगर गढ़ी पुलिस द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी एवं महिला उप निरीक्षक रश्मि मलिक के नेतृत्व में टीम ने थाना क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया। इस दौरान साइबर अपराधों से बचाव के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग रहने, किसी भी प्रकार की उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करने तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस टीम ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना प्राथमिकता है और इसके लिए मिशन शक्ति अभियान निरंतर जारी रहेगा। अभियान के अंत में महिलाओं ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए उपयोगी बताया।

एमएमएमयूटी में गर्ल्स हॉस्टल का भूमि पूजन व शिलान्यास किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

लोक तंत्र की शान

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के बाद बेटियों की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों से बीते नौ सालों में महिला श्रम शक्ति तीन गुना बढ़ी है। वुमेन वर्क फोर्स का आंकड़ा 12 से बढ़कर 36 प्रतिशत को पार कर चुका है। वर्ष 2017 से पहले महिला सुरक्षा जहां एक बड़ी चुनौती थी, वहीं अब बिना भय के महिलाओं का तेजी से कामकाजी होना समाज में सुरक्षा का एक मानक बना है। सीएम योगी बुधवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) में 144 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल के भूमिपूजन एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह गर्ल्स हॉस्टल, पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सीएसआर फंड से बनवाया जाएगा। इसके निर्माण पर 13.67 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने एमएमएमयूटी में 4.67 करोड़ रुपये की लागत से बनी साइबर फोरेंसिक रिसर्च लैब का उद्घाटन भी किया और रिसर्च एक्सीलेंस पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक पुस्तिका का अनावरण भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी सुरक्षित हो, उसका सम्मान हो और वह स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होकर नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सके, इस दृष्टि से उसी प्रकार की सुविधाएं देना आज की आवश्यकता है। इसे ही ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार हर बड़े महानगर में कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण कर रही है। किसी भी समाज में सुरक्षा का मानक यही है कि महिलाएं बिना भय घर से बाहर निकल सकें। 2017 के बाद सरकार की तरफ से इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम सबके सामने हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे अंडरपास पर भीषण सड़क हादसे मे युवक की मौत

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर। थाना सैदनंगली में गंगा एक्सप्रेसवे मार्ग के निकट एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान राहुल पुत्र सतपाल सिंह निवासी ग्राम निरयावली भूड़ के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, राहुल पुत्र सतपाल 40 वर्ष अपनी पत्नी काजल को ससुराल से लेने के लिए ग्राम हैबतपुर, कोतवाली हसनपुर जा रहा था। जैसे ही वह उझारी बुरावली रोड पर पहुंचा, तभी तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना सैद नगली अध्यक्ष विकास शेरावत तथा उझारी चौकी इंचार्ज अनिल त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे पंचनामा भर शव को पीएम के लिए भेज दिया पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर थाने ले गई। बताया जा रहा है कि राहुल पांच भाइयों में तीसरे नंबर का था। वह अपने पीछे पत्नी काजल मां ज्ञानवती और तीन साल का बेटा मयंक को रोता बिलखता छोड़ गया हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। थाना अध्यक्ष विकास सेहरावत ने बताया कि अज्ञात आरोपी ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर वैधानिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है।

एआईएमआईएम नेताओं को कोर्ट से राहत, नूर मोहम्मद पाशा बोले-"हमें न्याय पर पूरा भरोसा था"

लोक तंत्र की शान

संभल/मेरठः मेरठ में एआईएमआईएम के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महताब चौहान, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी और महानगर सचिव रजी सिद्दीकी को अदालत से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने की खबर से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया और समर्थकों ने राहत की सांस ली। इस पूरे घटनाक्रम पर संभल जिले के एआईएमआईएम युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नूर मोहम्मद पाशा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "देश में न्यायपालिका आज भी पूरी तरह मजबूत और सक्रिय है। हमें पहले से ही न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज हमारे पदाधिकारियों को जमानत मिलना इसी विश्वास का प्रमाण है।" उन्होंने आगे कहा कि एआईएमआईएम हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून का सम्मान करने वाली पार्टी रही है। "हमें यकीन था कि सच्चाई सामने आएगी और हमारे नेताओं को न्याय मिलेगा," उन्होंने कहा। जमानत की खबर मिलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं अन्य पदाधिकारियों ने भी इसे न्याय की जीत बताया और कहा कि पार्टी आगे भी जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी।

उपनिरीक्षक रश्मि मलिक ने महिलाओं को कानून और अधिकारों की दी अहम जानकारी

लोक तंत्र की शान

सम्भल/सिरसी थाना क्षेत्र हजरतनगर गढ़ी में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर एक प्रभावशाली जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महिला उपनिरीक्षक रश्मि मलिक ने महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनों और सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई मजबूत कानून बनाए गए हैं।

महिलाओं के कानूनी अधिकार (Legal Rights)

घरेलू हिंसा से सुरक्षा

घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं को किसी भी प्रकार की मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और गाली-गलौज से सुरक्षा प्राप्त है। महिला को घर से निकालना गैरकानूनी है।

दहेज के खिलाफ अधिकार

दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेना-देना अपराध है।

कार्यस्थल पर सुरक्षा

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत नौकरी के स्थान पर छेड़छाड़ या गलत व्यवहार पर सख्त कार्रवाई होती है।

समान वेतन का अधिकार

महिलाओं को पुरुषों के बराबर काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है।

हेल्पलाइन और त्वरित सहायता

1090 (UP Women Power Line)

181 (महिला हेल्पलाइन)

112 (आपातकालीन सेवा)

किसी भी परेशानी में महिलाएं तुरंत इन नंबरों पर संपर्क कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष योजनाएँ

मिशन शक्ति – महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए अभियान

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना – बेटियों की शिक्षा और पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता

निराश्रित महिला पेंशन – विधवा और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहयोग

महिला डेस्क – हर थाने में महिला पुलिस की सुविधा, जहां शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाता है

भारत सरकार की योजनाएँ

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ – बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा

सुकन्या समृद्धि योजना – बेटियों के भविष्य के लिए बचत योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना – महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन

महिला ई-हाट – महिलाओं को ऑनलाइन रोजगार और व्यापार का अवसर

महिलाओं के अन्य महत्वपूर्ण अधिकार

संपत्ति में बराबर हक

शादी और तलाक का अधिकार

मुफ्त कानूनी सहायता (Legal Aid)

गर्भावस्था में नौकरी सुरक्षा (Maternity Leave)

शिकायत कहाँ करें?

नजदीकी पुलिस थाना

महिला हेल्पलाइन (1090 / 181)

उत्तर प्रदेश सरकार की महिलाओं के लिए प्रमुख योजनाएँ-मिशन शक्ति – महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए चलाया जा रहा व्यापक अभियान। मुंगला योजना – बेटियों की शिक्षा और पालन-पोषण के लिए चरणबद्ध आर्थिक सहायता। निराश्रित महिला पेंशन योजना – विधवा और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। महिला सामर्थ्य योजना – महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार और प्रशिक्षण की सुविधा। महिला डेस्क (हर थाना) – थानों में महिला पुलिस की विशेष सुविधा, जहां महिलाओं की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाता है। वन स्टॉप सेंटर (सखी केंद्र) – हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर कानूनी, चिकित्सीय और काउंसलिंग सहायता। पिंक पेट्रोलिंग / एंटी रोमियो स्क्वॉड – सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष पुलिस व्यवस्था।

जिला महिला कल्याण अधिकारी कोर्ट या महिला आयोग-कार्यक्रम के अंत में महिला उपनिरीक्षक रश्मि मलिक ने महिलाओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों को पहचानें, किसी भी अन्याय को सहन न करें और तुरंत कानून की मदद लें।

संक्षिप्त समाचार

रामनवमी से पहले वैशाली पुलिस ने किया दंगा कंट्रोल प्रैक्टिस

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। आगामी रामनवमी पर्व के मद्देनजर वैशाली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से विशेष दंगा नियंत्रण अभ्यास (Riot Drill) का आयोजन किया। यह अभ्यास पुलिस केंद्र, हाजीपुर में किया गया, जिसमें जिले की सभी क्विक रिस्पांस टीम (QRT) के जवानों और अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अभ्यास के दौरान, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न चरणों का पालन किया गया। सर्वप्रथम मौखिक चेतावनी दी गई। इसके बाद स्थिति की गंभीरता के अनुसार न्यूनतम बल प्रयोग की नीति अपनाते हुए लाठी बल का प्रयोग किया गया। आगे, स्थिति के अनुरूप वाटर कैनन का उपयोग किया गया। अंततः, टियर गैस के प्रयोग द्वारा भीड़ को नियंत्रित और तितर-बितर करने का अभ्यास कराया गया। यह आयोजन वैशाली पुलिस अधीक्षक के. विक्रम सिहाग के निर्देश पर किया गया था। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस बल को तैयार रखना है।

छठ पूजा के दौरान तीन युवक गंगा में डूबे, पटना सिटी के दमराही घाट पर दो शव मिले, एक लापता

लोकतंत्र की शान : पटना। पटना सिटी के दमराही घाट पर बुधवार सुबह छठ पूजा के दौरान गंगा नदी में तीन युवक डूब गए। इनमें से दो के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे युवक की तलाश जारी है। यह घटना मालसलामी थाना क्षेत्र में हुई। मृतकों की पहचान 18 वर्षीय गणेश कुमार और 19 वर्षीय रोहित कुमार के रूप में हुई है। ये दोनों हनुमान नगर, कंकड़बाग के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, छठ पर्व के अवसर पर दमराही घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इसी दौरान तीन युवक गंगा नदी में स्नान करने उतरे। नदी की गहराई और तेज धारा के कारण वे संतुलन खो बैठे और डूबने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से दो युवकों को गंगा नदी से बाहर निकाला गया। उन्हें तत्काल नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (NMCH) के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के दौरान डूबने वाला तीसरे युवक लापता है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। मालसलामी थाना प्रभारी ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीम की मदद से गोताखोरों द्वारा गंगा नदी में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन ने छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं से नदी में उतरते समय सावधानी बरतने और केवल निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान करने की अपील की है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

महावीर मंदिर में अयोध्या से आयेंगे पुजारी

लोकतंत्र की शान : पटना। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। इस बार 27 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। इसके लिए पटना के मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही है। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में रात 2 बजे ही मंदिर का पट खुल जाएगा। पट खुलते ही 15 मिनट आरती होगी। आरती खत्म होते ही प्रसाद चढ़ाने और दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो 27 मार्च की रात होने वाली आरती तक चलेगा। इस बार पूजा के लिए अयोध्या से पुजारी बुलाए जाएंगे। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए श्रद्धालुओं की भीड़ पर नजर रखी जाएगी। महावीर मंदिर में नैवेद्यम लड्डू के लिए कोई काउंटर नहीं रहेगा। सभी काउंटर बाहर में रहेंगें। विभिन्न जगहों पर करीब 15 नैवेद्यम लड्डू काउंटर की व्यवस्था की जा रही है। मंदिर के समीप से वीर कुंवर सिंह पार्क तक काउंटर रहेगा। इस बार 24 हजार किलो नैवेद्यम तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। 18 हजार किलों नैवेद्यम बनाकर तैयार रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर और 6 हजार किलो और बनाने की तैयारी रखी गई। बीते वर्ष भी 18 हजार किलो नैवेद्यम तैयार करके रखा गया था। उसी के मद्देनजर इस बार 24 हजार किलों नैवेद्यम तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। राम नवमी के दिन लोहे और बांस की बैरिकेडिंग की जा रही है। धूप से बचाव के लिए छावनी बनाई जा रही है और पूरे रास्ते में समुचित लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतार रहेगी। इसके अलावा कई जगहों पर बड़ा एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। इन एलईडी पर लाइव पूजा देखने की व्यवस्था होगी। पानी, शर्बत और मोबाइल शौचालय की व्यवस्था रहेगी। मेडिकल कैंप, एंबुलेंस भी मौजूद रहेगी। इसके साथ ही सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। सुरक्षा में सरकारी और प्राइवेट सुरक्षाकर्मियों की मदद ली जाएगी। सरकारी के अलावा करीब 100-120 प्राइवेट सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे जिससे कतार में लगे भक्तों की भीड़ को समुचित तरीके से नियंत्रित किया जा सके। रामनवमी के रोज कितने भक्त आए इसकी गिनती के लिए नई तकनीक लगाने की कोशिश हो रही है, जिससे हेड काउंट किया जा सके।

यूपी मॉडल से सीखेंगे बिहार के मुखिया

लोकतंत्र की शान : पटना। बिहार के पंचायती राज प्रतिनिधियों (मुखिया) का उत्तर प्रदेश के मॉडल ग्राम पंचायतों का चार दिवसीय अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। पटना से शुरू हुए इस दौरे में 80 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं और नवाचारों को करीब से समझा। यह एक्सपोज़र विजिट राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2024-25 के तहत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को बेहतर प्रशासन और विकास मॉडल से अवगत कराना था। इस चार दिवसीय एक्सपोज़र विजिट के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पटना से अपनी यात्रा प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने वाराणसी स्थित रसूलपुर ग्राम पंचायत का भ्रमण किया। यहां जमीनी स्तर पर लागू की गई योजनाओं और विकास कार्यों का अध्ययन किया गया। यात्रा के तीसरे दिन प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा, जहां पलिया लोहानी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से संवाद किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत राम मंदिर का भी दौरा किया गया, जिससे , जिससे प्रतिनिधियों को स्थानीय सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश की समझने का अवसर मिला। इस अध्ययन दौरे के दौरान प्रतिनिधियों ने संबंधित राज्यों के पंचायती राज अधिनियम/नियम, संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषयों के विकेंद्रीकरण, गतिविधि मानचित्रण, थीमैटिक जीपीडीपी, जल प्रबंधन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्व-राजस्व स्रोत एवं कर प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। प्रतिनिधियों ने विभिन्न राज्यों में अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन किया और भविष्य में इन्हें अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों में लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि इस तरह के अध्ययन दौरे से स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने में मदद मिलेगी।

बॉडीगार्ड्स के साथ कॉलेज में पढ़ाने पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी

लोकतंत्र की शान , पटना: बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बुधवार सुबह पटना के AN कॉलेज पहुंचे। मंत्री जी इस बार किसी आधिकारिक दौरे पर नहीं थे, बल्कि बतौर प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेने आए थे। खास बात यह रही कि जिस बिल्डिंग का निर्माण उन्होंने मंत्री रहते हुए कराया था, उसी भवन में वे आज पढ़ाने पहुंचे। इतना ही नहीं क्लास लेने से पहले उन्होंने खुद सेलेबस लेकर पढ़ाई भी की। कॉलेज पहुंचने के बाद अशोक चौधरी ने कहा, "बहुत कम लोग होते हैं जो मंत्री रहते हुए प्रोफेसर के रूप में क्लास लेते हैं। छात्रों से भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा।" जब उनसे पूछा गया कि जिस बिल्डिंग को उन्होंने बनवाया, उसी में पढ़ाने आए हैं, कैसा लग रहा है, तो इसपर उन्होंने कहा, "ये सब महादेव का आशीर्वाद है।" अशोक चौधरी ने X पर लिखा पिता जी ने हमारे लिए जो सपना देखा था, आज उसे जीने और साकार करने का अवसर मिला है। बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर हमारी कोशिश रहेगी कि छात्रों को पॉलिटिकल साइंस सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि समाज, लोकतंत्र और जीवन को समझने का सशक्त माध्यम के रूप में पढ़ा सकूं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर पाऊं।

संबल योजना के तहत 40 दिव्यांगजनों को निःशुल्क बैट्री चालित ट्राइसाइकिल वितरित

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाता: जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, सहरसा द्वारा संचालित संबल योजना के तहत बुधवार को सहरसा स्टेडियम में निःशुल्क बैट्री चालित ट्राइसाइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी श्री दीपेश कुमार, उप विकास आयुक्त श्री गौरव कुमार एवं अपर समाहर्ता श्री निशांत द्वारा चयनित 40 दिव्यांगजनों के बीच ट्राइसाइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने पात्र दिव्यांगजनों को योजना का लाभ उठाने हेतु अधिक से अधिक आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम में सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग श्री राजीव रंजन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सहरसा जिले को 130 बैट्री चालित ट्राइसाइकिल वितरण का लक्ष्य दिया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 458 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि आज 40 लाभार्थियों के बीच ट्राइसाइकिल का वितरण किया गया है। साथ ही उन्होंने अन्य सहायक उपकरण जैसे ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, सीपी चेयर आदि के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। इच्छुक दिव्यांगजन विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, समाहरणालय सहरसा से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पात्रता शर्तें: आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होनी चाहिए। वार्षिक आय अधिकतम दो लाख रुपये तक होनी चाहिए। छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षणिक संस्थान की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज: आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक पहचान पत्र/रोजगार संबंधी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं पासपोर्ट साइज फोटो। कार्यक्रम में जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी श्री आलोक कुमार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

पटना में 60 एसिड अटैक पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

लोकतंत्र की शान , पटना

बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी की ओर से 29 मार्च को पटना में एसिड अटैक पीड़ितों के लिए एक विशेष जागरूकता एवं सहायता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह पहल नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मिनिमम एक्शन प्लान के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों में कानूनी जागरूकता बढ़ाना है।

मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर आयोजन: प्राधिकरण के मेंबर सेक्रेटरी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा।

60 एसिड अटैक पीड़िताओं की भागीदारी: कार्यक्रम में राज्यभर से लगभग 60 एसिड अटैक पीड़िताएं हिस्सा लेंगी। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा पीड़ितों का आंकड़ा एकत्र कर उन्हें आमंत्रित किया गया है, ताकि वे इस पहल का लाभ उठा सकें। इस दौरान सभी पीड़िताओं को लगभग 3 लाख रुपये की न्यूनतम मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि मुख्य न्यायाधीश द्वारा वितरित की जाएगी। इसके अलावा, विक्टिम कंपेंसेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित अतिरिक्त मुआवजा राशि भी पीड़ितों को दी जाएगी। धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि पीड़ितों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना भी है। कार्यक्रम में कानूनी सहायता, पुनर्वास योजनाओं और सरकारी सहयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। उन्होंने बताया कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत सालभर विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, ताकि जरूरतमंदों तक न्याय और सहायता की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

रामनवमी एवं चैती दुर्गापूजा 2026 को लेकर प्रशासन सतर्क, 142 दंडाधिकारी-पुलिस पदाधिकारी तैनात

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाता: आगामी रामनवमी पर्व एवं चैती दुर्गापूजा 2026 के मद्देनजर जिले में विधि-व्यवस्था के सुचारु संधारण हेतु बुधवार को स्थानीय प्रेक्षा गृह में जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु की संयुक्त अध्यक्षता में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर अनुमंडल क्षेत्र में चिन्हित स्थलों पर कुल 98 दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र में 44 दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की गई है। सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान एवं आपात स्थिति में शीघ्र कार्रवाई के उद्देश्य से जिला नियंत्रण कक्ष 26 मार्च से 28 मार्च 2026 तक लगातार कार्यशील रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया की सतत निगरानी की जा रही है और इसके माध्यम से आपसी सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आसन्न पर्व-त्योहार के दौरान डीजे के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को अपने दायित्वों का ईमानदारी एवं सतर्कता के साथ निर्वहन करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं सिमरी बख्तियारपुर, एसडीपीओ (मुख्यालय) सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

रहीमपुर गोठ में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भवन का उद्घाटन, शिक्षा के प्रसार पर जोर

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाता: सौर बाजार अंचल अंतर्गत रहीमपुर गोठ में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन बुधवार को जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक शिक्षित व्यक्ति समाज, राज्य और राष्ट्र के समेकित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें, जिससे एक विकसित समाज का निर्माण संभव हो सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर समाहर्ता श्री निशांत ने कहा कि इस विद्यालय के शुरू होने से क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का बेहतर अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिले में चिन्हित क्षेत्रों में प्रत्येक दो किलोमीटर पर विद्यालय निर्माण की योजना प्रस्तावित है, जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा सर्वेक्षण कार्य जारी है। इससे क्षेत्र में शिक्षा के व्यापक प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री हेमचंद्र ने कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने कहा कि लगभग 1500 की आबादी वाले इस क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना से शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय निर्माण हेतु भूमि दान करने वाले श्री जयराम प्रसाद सिंह सहित जिलाधिकारी

श्री दीपेश कुमार एवं अपर समाहर्ता श्री निशांत को पाग एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। अन्य संबंधित अधिकारी एवं गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

सहरसा में LPG वितरण व PNG कनेक्शन कार्य की समीक्षा, पाइपलाइन बिछाने में तेजी लाने के निर्देश

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाता: जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण की वर्तमान स्थिति एवं पीएनजी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इसी क्रम में जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार ने नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत डुमरैल के यादव चौक का निरीक्षण किया, जहां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) द्वारा पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बताया गया कि वर्तमान में कार्यकारी एजेंसी द्वारा उक्त स्थल पर डीआरएस (DRS) कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने शेष ढलाई कार्य को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने पीएनजी गैस की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्य को युद्ध स्तर पर तेज करने को कहा। जानकारी के अनुसार, अब तक लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष चिन्हित स्थानों पर पाइप बिछाने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन द्वारा इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त श्री गौरव कुमार, अपर समाहर्ता श्री निशांत सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

दनियावां के सूर्य मंदिर तालाब में डूबा किशोर, मौत

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना के दनियावां थाना क्षेत्र स्थित सूर्य मंदिर तालाब में छठ महापर्व के समापन के दौरान एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। यह घटना बुधवार सुबह दूसरे अर्घ्य के समय हुई, जिससे पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। मृतक की पहचान शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के छोटी केवई गांव निवासी अखिलेश यादव के 18 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार के रूप में हुई है।

नहाते समय गहरे पानी में गया, डूबने से मौत: ग्रामीणों के अनुसार, आकाश अपने एक रिश्तेदार के घर छठ पूजा में शामिल होने दनियावां आया था। बुधवार सुबह वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सूर्य मंदिर तालाब घाट पर पहुंचा। अर्घ्य और पूजा के बीच वह तालाब में स्नान करने लगा। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया, जिसका पता किसी को नहीं चल पाया।

पूजा संपन्न होने के बाद परिजन अपने-अपने घर लौट गए। जब काफी देर तक आकाश घर नहीं पहुंचा, तब परिजनों को किसी अनहोनी का संदेह हुआ। वे तुरंत घाट पर वापस पहुंचे और तालाब के पानी में उसकी तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद आकाश का शव पानी के अंदर से बरामद हुआ। शव मिलते ही घाट पर मौजूद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही दनियावां पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया।

निशांत कुमार ने विधायक-कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक

लोकतंत्र की शान , पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उनका पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। निशांत जिला अध्यक्ष और सारण प्रमंडल के अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। चेतन आनंद, रुहेल रंजन, ऋतुराज कुमार के साथ जेडीयू के कई और भी विधायक, एमएलसी संजय गांधी भी मौजूद हैं। वहीं, बैठक के बाद निशांत ने पिता के फिर से जेडीयू प्रेसिडेंट चुने जाने पर बधाई दी। निशांत ने कहा, हमलोग पिता जी के ही मार्गदर्शन पर चलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि पार्टी के वरीय नेता-कार्यकर्ता या प्रतिनिधी हों, पार्टी सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे। निशांत कुमार फिलहाल पार्टी कार्यालय के हर रूम में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं।

11 मार्च को अचानक पहुंचे थे जदयू ऑफिस: इससे पहले निशांत कुमार बुधवार 11 मार्च को अचानक से JDU ऑफिस पहुंचे थे। जहां JDU के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया था। इस दौरान कार्यकर्ताओं के 'बिहार का CM कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो' के नारे लगाए थे। निशांत के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और उनके समर्थन में नारे लगाने लगे थे। निशांत करीब 30 मिनट तक पार्टी ऑफिस में रुके थे उनके निकलने के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने उनकी आरती उतारी।

जदयू बोली- गिरधारी यादव की सदस्यता खत्म हो

पार्टी ने कहा- बेटे को राजद से चुनाव लड़वाया, उसके लिए प्रचार भी किया, लोकसभा स्पीकर एक्शन लें

लोकतंत्र की शान , पटना

बांका से JDU के सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ पार्टी एक्शन लेने के मूड में है। उनकी लोकसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। लोकसभा में जनता दल (यूनाइटेड) के ही नेता दिलेश्वर कामत ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर ऐक्शन लेने की गुजारिश लोकसभा स्पीकर से की है। दिलेश्वर कामत ने जदयू सांसद गिरधारी यादव को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की है। गिरधारी यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। दिलेश्वर कामत ने कहा कि विधानसभा में गिरधारी यादव ने अपने बेटे को राजद से चुनाव लड़वाया था।

इस दौरान उन्होंने राजद के लिए प्रचार किया था। उससे पहले भी वो पार्टी के खिलाफ काम करते रहे हैं। इन सब बातों को लेकर लोकसभा स्पीकर को कार्रवाई करने के लिए पार्टी की तरफ से कहा गया है। वहीं जदयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि, गिरधारी यादव ने राजद की टिकट पर अपने बेटे को मैदान में उतारा था। जदयू सांसद ने खुद बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया था। इसके प्रमाण मिले हैं। इसी आधार पर हमारे

संसदीय नेता ने उनको अयोग्य करने का आवेदन सौंपा है। अब इस पर स्पीकर विचार करेंगे। गिरधारी यादव को पिछले साल JDU ने गिरधारी यादव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। यह कारण बताओ नोटिस उन्हें SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर दिए गए बयानों के बाद भेजा गया था। नोटिस के मुताबिक SIR पर सांसद गिरधारी यादव के बयान को पार्टी अनुशासन के खिलाफ मानती है। इसको लेकर JDU ने सांसद से जवाब तलब किया था। इसके साथ ही नोटिस में यह बताया गया था कि जवाब नहीं देने पर एक्शन भी लिया जाएगा। 'समृद्धि यात्रा' के दौरान भी बांका में मंच पर तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन गिरधारी यादव की गैरमौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए थे।

गिरीधारी यादव ने क्या बयान दिया था: विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में SIR हुई थी। गिरधारी यादव ने अपने बयान में कहा था कि अगर लोकसभा चुनावों के लिए वोटर लिस्ट सही थे तो कुछ ही महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए यह गलत कैसे हो गया? उन्होंने कहा था कि क्या मैं गलत वोटर लिस्ट के आधार पर सांसद बना हूं।

चुनाव आयोग पर भी साधा था निशाना: JDU सांसद गिरिधारी यादव ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से SIR की प्रक्रिया तब शुरू की गई है जब बिहार के लोग बाढ़ परेशान हैं। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा था कि SIR 6 चुनाव से पहले के बजाय 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था। इन्हीं बयानों को लेकर पार्टी ने सांसद को जो नोटिस भेजा था, उसमें कहा गया था कि, जदयू ने हमेशा चुनाव आयोग का समर्थन किया है। लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर उनकी टिप्पणी पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी है।

RJD से सांसद के बेटे ने लड़ा था चुनाव: गिरिधारी यादव के बेटे चाणक्या प्रकाश रंजन ने राजद की टिकट पर बांका के बेलहर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन वो चुनाव हार गए थे।

संक्षिप्त समाचार

ऑपरेशन शिकंजा'' के तहत कटनी पुलिस की 39 अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई

लगभग 55 हजार मूल्य की 303 पाव अवैध देशी /विदेशी एवं 67 लीटर कच्ची शराब जब्त

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेशः कटनी- जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से कटनी पुलिस द्वारा संचालित विशेष अभियान "ऑपरेशन शिकंजा" के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संतोष डेहरिया के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन अभियान चलाते हुए 39 प्रकरणों में कुल 39 अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से — लगभग 55,000/- रुपये मूल्य के 303 पाव अवैध देशी/विदेशी शराब एवं 67 लीटर कच्ची शराब को जप्त किया गया है। उक्त कार्रवाई में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कटनी पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि यदि कहीं भी अवैध शराब के निर्माण या विक्रय की सूचना हो, तो तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 7587615946 पर सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।

एक तरफ डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी का सख्त एक्शन, दूसरी तरफ टीएसआई की छत्र छाया में उड़ रहीं नियमों की धज्जियां

आहिमामऊ अंडरपास के नीचे अवैध डग्गामार बस, ई-रिक्शा और अर्टिगा वाहनों का अड्डा, जनता भीषण जाम से बेहाल

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में एक ओर डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार सख्त अभियान चलाकर अवैध डग्गामार बसों, अवैध ई-रिक्शा और अवैध चार पहिया वाहनों (अर्टिगा) पर कानूनी हंटर चला रही हैं, ताकि शहर का ट्रैफिक सुचारु रूप से चलता रहे और आम जनता को जाम की समस्या से राहत मिल सके। लेकिन दूसरी ओर, आहिमामऊ अंडरपास के नीचे स्थिति बिल्कुल उलट नजर आ रही है। यहां अवैध डग्गामार बस स्टैंड, अवैध ई-रिक्शा स्टैंड और अर्टिगा चार पहिया वाहनों का अवैध अड्डा खुलेआम संचालित हो रहा है, जिससे रोजाना भीषण जाम लग रहा है और यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जहां एक तरफ ट्रैफिक विभाग शहर में नियम-कानून का पालन कराने के लिए अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक टीएसआई की छत्रछाया में अवैध बस संचालक, ई-रिक्शा चालक और अर्टिगा वाहन चालक खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सड़क किनारे सवारियां भरने, अवैध पार्किंग और मनमाने ढंग से वाहनों की कतार लगाने से आम राहगीर, स्कूली बच्चे, नौकरीपेशा लोग और एम्बुलेंस तक प्रभावित हो रही हैं। सूत्रों के अनुसार, अवैध डग्गामार बसों, ई-रिक्शा और चार पहिया वाहनों से जुड़े संचालकों से हर माह मोटी रकम वसूले जाने की भी चर्चा है, जिसके चलते यह अवैध खेल लगातार फल-फूल रहा है।

अब सवाल यह उठता है कि- जब डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी शहर में सख्त कार्रवाई कर रही हैं, तो फिर आहिमामऊ में किसके संरक्षण में चल रहा है यह अवैध खेल? क्या ट्रैफिक टीएसआई की भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी? कब मिलेगी जनता को जाम और अवैध स्टैंड से राहत?

एक तरफ डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी का सख्त एक्शन... दूसरी तरफ टीएसआई की छत्रछाया में अवैध डग्गामार बस, ई-रिक्शा और अर्टिगा वाहनों का खेल जारी! आहिमामऊ अंडरपास के नीचे रोज लगता है भीषण जाम! ट्रैफिक नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां! आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है यह अवैध टैम्पु स्टैंड

कौशल विकास से तेज होगी आर्थिक रफ्तार, ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य पर योगी सरकार का फोकस

लोकतंत्र की शान : लखनऊ। उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देने के लिए योगी सरकार कौशल विकास को केंद्र में रखकर तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागीय योजनाओं की प्रगति और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का फोकस युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित करना है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के सशक्तीकरण को लेकर बैठक में विशेष जोर दिया गया। टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से आधुनिक प्रशिक्षण मॉडल विकसित करने और उद्योग आधारित स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता को उद्योगों की मांग के अनुरूप बनाना समय की जरूरत है, जिससे युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जा सके।

भू-माफियाओं के आगोश में शहर से लगे गांव,प्लाट बेचने नहर को पाटने का आरोप

» शहर से लगे पड़ैनिया गांव का मामला

» सरकार के जल गंगा संवर्धन अभियान को प्रभावित करने की रणनीति

लोकतंत्र की शान (कु ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। एक तरफ सरकार जल स्त्रोतों को संरक्षित करने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चला रही है वहीं अपने निजी स्वार्थ में लिप्त भू-माफिया द्वारा पुरानी नहर को ही पाटकर सडक़ बना दिया गया। यह मामला शहर से लगे ग्राम पंचायत क्षेत्र पड़ैनिया का सामने आया है। शहर के समीपी होने के कारण इस क्षेत्र में काफी तेजी के साथ प्लाटिंग कर भू-खंड बेंचने का सिलसिला चल रहा है। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार शहरी क्षेत्र एवं उससे लगे इलाके में भू-खंड बेंचने से पूर्व 15-30 फिट की सडक़ होना अनिवार्य है। इसी वजह से भू-माफिया द्वारा अपनी निजी स्वार्थसिद्धि के लिए कमर्जी हाउस के आगे बटौली रोड पर स्थित जल संसाधन विभाग की पुरानी नहर को ही पाटकर चौड़ी सडक़ बना दी गई। जिससे इससे लगे इलाके में भू-खंड मनमानी कीमतों में बेंचने में मदद मिल सके। हैरत की बात तो यह है कि सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका भी इस मामले में पूरी तरह से संदिग्ध है। विभाग की पुरानी नहर को पाटने का जब काम किया जा रहा था तो इसकी सूचना कुछ क्षेत्रीय लोगों द्वारा विभाग को भी दी गई लेकिन उनके द्वारा नहर की पटाई रोंकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। लिहाजा जेसीबी मशीन के द्वारा कुछ ही घंटों में नहर को पूरी तरह से पाटकर वहां चौड़ी सडक़ बना दी गई। सडक़ के ऊपर गिट्टी का चूरा डालकर इस सडक़ को व्यवस्थित कराने का काम आनन-फानन में कर दिया गया। जल संसाधन विभाग की पुरानी नहर को पाटकर सडक़ बनाने के मामले में ग्राम पंचायत पड़ैनिया के सरपंच-सचिव पर भी आरोप लग रहे हैं। कुछ ग्रामीणों का कहना था कि सिंचाई विभाग की पुरानी नहर को पाटने की जानकारी ग्राम पंचायत के इन नुमाइंदों को अच्छे से होने के बाद भी इनके द्वारा रोंकने का कोई प्रयाश नहीं किया गया न ही इस मामले की सूचना समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों को दी गई। जिससे नहर की पटाई का काम पूरी तरह से रोंका जा सके।

पुरानी नहरों का वजूद खतरे में

सीधी शहर एवं इसके आसपास सिंचाई के लिए कई पुरानी नहरें मौजूद हैं। यह नहरें जहां से भी गुजर रही हैं वहां की भूमि पूरी तरह से शासकीय है। कई नहरों में लंबे समय से पानी को छोंडऩा बंद कर दिया गया है इस वजह से भू-माफिया की नजर बंद पड़ी पुरानी नहरों एवं उससे लगी भूमि पर पूरी तरह से बनी हुई है। शहर के गोपालदास बांध से संबद्ध कई ऐसी पुरानी नहरें हैं जिनमें पानी वर्षों से छोंडऩा बंद कर दिया गया है। वहां भी नहर एवं उससे लगी भूमि पर तेजी के साथ अतिक्रमण किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग की इन बंद पुरानी नहरों की खोज-खबर लेने वाला कोई नहीं है। इसी वजह से अतिक्रमणकारी सबसे पहले कुछ लोगों को कब्जा करने के लिए उकसाते हैं। ऐसे अतिक्रमणकारी मौके पर बांस-बल्ली लगाकर धीरे-धीरे अतिक्रमण शुरू करते हैं। बाद में उस स्थान पर टीनशेड़ के माध्यम से छत डालकर दीवाल बनाने का काम शुरू हो जाता है। पड़ैनिया एवं बटौली तथा उससे लगे इलाके में कई किलोमीटर बंद पुरानी नहरें हैं। इन नहरों के भूमि की कीमत आज करोड़ों में हैं। इसी वजह से बंद पड़ी पुरानी नहरों पर अवैध कब्जा करने का सिलसिला काफी तेजी के साथ शुरू है। जल संसाधन विभाग का अमला बंद पड़ी पुरानी नहरों की सुरक्षा को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रहा। लिहाजा उनकी शिथिलता के चलते अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण का दौर सालों से निर्बाध रूप से चल रहा है।

रामनवमी एवं चैत्र नवरात्रि समापन पर पुलिस सतर्क, सुरक्षा व्यवस्थाओं का व्यापक निरीक्षण

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी - आगामी रामनवमी पर्व एवं चैत्र नवरात्रि समापन के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में कटनी पुलिस द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पच्चीसिया सहित पुलिस अधिकारियों द्वारा जुलूस मार्गों, पूजा स्थलों एवं विसर्जन स्थलों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। रामनवमी जुलूस को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने हेतु विभिन्न मार्गों का भौतिक सत्यापन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान पूजा समितियों, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित किया गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा जुलूस मार्ग में अवरोध हटाने, विद्युत तारों को सुरक्षित ऊंचाई पर करने, वॉलिंटियर तैनात करने एवं यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए गए। सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने एवं दुकानदारों को नियमों का पालन करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

चरित्र संदेह में पत्नी को मौत के घाट उतारने वाला आरोपी गिरफतार

सेमरिया पुलिस ने किया हत्यारोपी को बेनकाब

लोकतंत्र की शान (कु ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। जिले के सेमरिया थाना के बढ़ौरा गांव में चरित्र संदेह को लेकर पति ने पत्नी को लाठी से पीटकर हत्या करने के बाद फरार हो गया जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं एसडीओपी चुरहट रवि प्रकाश कौल के मार्गदर्शन में, थाना सेमरिया पुलिस ने हत्यारोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर फरार हुए आरोपी पति को घटना के महज 20 घंटे के भीतर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है।

घटना का विवरण एवं कारणः दिनांक 24.03.2026 को ग्राम बढ़ौरा निवासी फरियादी मोनिक कुमार रावत (17 वर्ष) ने थाना सेमरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता मिथिला उर्फ ललवा रावत, उसकी माँ उमा रावत के चरित्र पर संदेह करते थे। इसी शक और रंजिश के चलते आरोपी ने मृतिका को लाठी-डंडों से बर्बरतापूर्वक मारपीट की, जिससे घटनास्थल पर ही उमा रावत की मृत्यु हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई एवं गिरफ्तारीः मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सेमरिया में अपराध क्रमांक 88/26, धारा 296बी, 351(3), 103(1) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी सेमरिया उनि. केदार परौहा के नेतृत्व में दो अलग-अलग विशेष टीमें गठित की गईं। इन टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से सघन दबिश दी और फरार आरोपी मिथिला उर्फ ललवा रावत (45 वर्ष) को घटना के महज 20 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

इनकी भूमिका सराहनीय-उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सेमरिया उनि. केदार परौहा, उनि. विकास सिंह, सउनि. भूपेंद्र बागरी, सउनि. टीडी रावत, प्र.आर. पंकज विश्वकर्मा, आर. विनीत सिंह एवं आर. मनीष शुक्ला की महत्वपूर्ण और सराहनीय भूमिका रही। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

भागवत कथा के विश्राम दिवस पर बोले कथा व्यास

» भागवत कथा की अनुक्रमणिका अद्भुत फलदायी -पं बालाव्यंकटेश

लोकतंत्र की शान (कु ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। शहर के शिवाजी नगर नौढ़िया सीधी में चल रही 19मार्च 2026से श्रीमद्भागवत कथा के पूर्णाहुति दिवस में कथा व्यास बालाव्यंकटेश महराज वृन्दावनोपासक का भगतगणों ने 25मार्च 2026 को माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत और व्यास पीठ की पूजा अर्चना प्रमुख यजवान भोला सिंह बघेल समरबहादुर सिंह बघेल,विनोद प्रताप सिंह बघेल और प्रमोदसिंह बघेल ने सपरिवार किया। कथा व्यास बालाव्यंकटेश महराज जी ने उपस्थित भक्तों को सम्बोधित करते हुए कहा कि श्रीमद्भागवत की अनुक्रमणिका श्रवण का अद्भुत फल होता है।जो भक्त लगातार सात दिन की कथा नही सुन पाते वो यदि मनसा बाचा कर्मणा सूत्रानुसार अनुक्रमणिका का श्रवण कर लेते हैं उनको सात दिवसीय फल मिल जाता है।कृष्ण सुदामा चरित्र का मार्मिक कथानक प्रस्तुत करते हुए व्यास जी ने बताया कि सुदामा जी साधना त्याग और अपने परम मित्र के प्रति अगाध प्रेम रखते थे।प्रसंग को रोचक बनाते हुए महराज जी ने कहा कि जब सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने तीन मुट्ठी चावल एक पुटकी में बाँधकर मित्र कृष्ण जी के पास सुदामा जी को भेजा तब भगवान सारा मर्म समझ गये।जैसे ही सुदामा जी चावल की पोटली अपनी कॉख में छिपाये हुए कृष्ण जी के पास गये वैसे ही कृष्ण जी ने पूछ लिया मेरी भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए। सुदामा जी संकोच के कारण मौन रहे किन्तु त्रिकालदर्शी भगवान उनकी कॉख से पोटली खींचकर जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तैसे ही रुक्मिणी जी ने कृष्ण का हाथ पकड़कर कहा -स्वामी ये क्या कर रहे हो?क्या तीनो लोक की सम्पति इनको देकर कंगाल बनना चाहते हो?तब भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि यह मेरे ऐसे समर्पित प्रेमी बाल सखा हैं इनको तीनों लोक का ऐश्वर्य दे दिया जाय तो भी मुझे लगेगा कि अभी अपने सखा को कुछ भी नही दिया। रुक्मिणी रानी के एक रोचक संवाद के उत्तर में श्रीकृष्ण जी ने कहा कि यह वही ब्राम्हण देवता हैं जो पत्र लेकर आये थे नही आप शिशुपाल के पास होती। फलतः सुदामा जी अद्भुत प्रेम के प्रतीक ही नही वल्कि प्रेम के सागर हैं भक्ति की सरिता हैं और आस्था के आकाश हैं। एक मजेदार कथानक देकर महराज जी ने बताया कि जब सुदामा जी महिमानी स्वागत सत्कार लेकर चलने लगे तब राज दरबार के कपड़े तक उनसे उतरवा लिए गये और पूरे शहर में मुनादी दिला दिये कि यह त्यागी महराज हैं कोई कुछ दान में देगा तो कंगाल हो जायेगा।सुदामा जी चलते चलते सोचे कि मित्र ने आव भाव और खातिरदारी तो बहुत किया किन्तु दिया कुछ नही। फिर मन ही मन सुदामा जी ये सोचे कि हो सकता है कि हमारा मित्र धन पाकर धन लम्पट न हो जाय इसलिए उन्होने चलते समय कुछ न दिया होगा।लेकिन भगवान भक्त के बस में होते आयें इसीलिए दयासिन्धु कहा गया है।श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि सुदामा जी के घर पहुँचते -पहुँचते उनका भव्य महल बनना चाहिए और सुशीला भाभी की नीद खुले तो उनको शीशमहल दिखे। सुदामा जी जब पहुँचे तो देखे कि उनकी कुटिया महल में परिवर्तित हो चुकी है।अभिप्राय यह कि कृष्ण सुदामा की मित्रता सम्पूर्ण जगत में एक निस्वार्थ श्रद्धा भक्ति की मिशाल बनी हुई है।अंत में महराज जी ने सुंदर सी प्रार्थना भागवत भगवान की किये कि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और फिर भागवत महराज जी का विसर्जन और विश्राम हुआ।शिवाजीनगर की यह एक महत्वपूर्ण कथा जनमानस में चर्चा का विषय बन गई। आज शहर के अनेक गणमान्य नागरिक,व्यापारी,पत्र कार,साहित्यकार और भगवत प्रेमी जन उपस्थित रहे।

मैहर के भटूरा में हुकुमचंद लाइम स्टोन खदान पर गंभीर आरोप, मचा बवाल

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ कटनी जबलपुर ,मध्य प्रदेश

मैहर के भटूरा क्षेत्र में संचालित हुकुमचंद लाइम स्टोन खदान इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में है। सूत्रों के मुताबिक खदान का संचालन स्वीकृत माइनिंग प्लान और स्कीम ऑफ माइनिंग के खुले उल्लंघन में किया जा रहा है। आरोप है कि जिले के खनिज विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से सब कुछ कागजों में "साफ-सुथरा" दिखाया जा रहा है। हकीकत में खदान से लेकर सड़कों तक कंपनी का तांडव नजर आ रहा है, जिससे पर्यावरण और आमजन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

महिला की मौत पर भड़के परिजन, झोलाछाप चिकित्सक पर लगाया लापरवाही का आरोप

लोकतंत्र की शान

» पैथालॉजी की आड़ में चला रहा था अवैध क्लीनिक,

» घटना मझौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोगीपहाडी की

सीधी। जिले के मझौली थाना क्षेत्र अंतर्गत झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कथित झोलाछाप डॉक्टर लंबे समय से पैथोलॉजी लैब की आड़ में अवैध रूप से क्लीनिक संचालित कर रहा था और मरीजों का इलाज भी कर रहा था। मिली जानकारी के अनुसार मृतिका नवानगर खडौरा निवासी साकेत परिवार की है, महिला के पेट में दर्द की शिकायत लेकर उसके पति सुखदीन साकेत उक्त झोलाछाप डॉक्टर के पास पहुंचे थे, जहां झोलाछाप डॉक्टर ने बिना किसी उचित जांच के ही दवाई कर दी, और अगले दिन महिला की मौत हो गई।

यह हैं पूरा मामला

घटना के संबंध में मृतिका के पति ने जानकारी देते हुए बताया हमारी पत्नी के पेट में दर्द था जिसको लेकर ए के डायग्नोस्टिक सेंटर में अजय केवट के पास ले गए जहां पत्नी को दो बॉटल और 3 इंजेक्शन लगाया और दवाई दिए ऑटो का किराया देकर घर भेज दिए इसके बाद उसको घर लेकर आ गए रात में कोई राहत तो नहीं हुई हमारी पत्नी को ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी हालत बिगड़ने पर अगले दिन सुबह खड़ौरा में स्थिति सौम्या मेडिकल में ले गए जहां उनके द्वारा बिना दवाई के वापस कर दिए बोले जहां पहले कराएं हैं वही ले जाएं तब हम लोगों ने जोगीपहाड़ी में स्थित क्लिनिक ए के डायग्नोस्टिक सेंटर में ले गए, महिला की हालत देख कथित डॉक्टर अजय केवट सरकारी अस्पताल में भेज दिया जिससे उसकी रास्ते में ही मौत हो गई।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

गलत दवा के चलते महिला की मौत से नाराज परिजनों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस ने मामले को संज्ञान लेते हुए मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराने के उपरांत परिजनों को सौंप दिया है। खास बात यह है कि मझौली अंचल में झोलाझाप डॉक्टरों की क्लीनिक गली गली में खुल गई है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते आए दिन गलत उपचार के चलते आए दिन लोगों की जान जा रही है।

साल भर में नहीं बना सके नाली व सड़क

» संविदाकारों की मनमानी आई सामने ,रुका नगर का विकास

» नगर वासियों ने लगाया विभागीय लापरवाही का आरोप

लोकतंत्र की शान (कु ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। नगर विकास के लिए निकाली गई निविदा को पाने के लिए संविदाकारों ने रेट की परवाह किए बिना ही टेंडर डाल दिया, सबसे कम रेट वाले को ठेका भी मिल गया, लेकिन निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए जो समयसीमा तय की गई थी उस ओर तनिक गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। जिसके चलते एक तरफ जहां नगर का विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है दूसरी तरफ नगर वासियों को तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। गौरतलब हो कि यह पूरा वाकया है जिले के नगर परिषद चुरहट का, जहां वार्ड क्रमांक दो एवं तीन में चल रहे नाली निर्माण कार्य को बीते चार माह से बंद कर दिया गया है, ऐसे में जहां मुहल्ले वासियों को पानी निकासी को लेकर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है वहीं सड़क पर संविदाकार द्वारा मैटेरियल डंप लोगों का आनाजाना प्रभावित कर रहा है।

विभाग पर उठ रहे सवाल

नगर परिषद के रहवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर में कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, जिसके संबंध में शिकायत भी कई बार स्थानीय प्रशासन से की गई लेकिन संविदाकारों की करेंसी के आगे लोगों की शिकायत प्रभावशाली नहीं हो रही है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि अगर समय रहते निर्माण कार्यों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले बरसात में लोगों की फजीहत हो जाएगी।

उधर पार्षद ने लिखा सीएमओ का पत्र

नगर परिषद चुरहट के वार्ड क्रमांक एक के पार्षद अफजल खान ने भी विकास कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए सीएमओ को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग उठाई है। पार्षद ने अपने वार्ड में तालाब चौडीकरण का कार्य मुख्यमंत्री अधोसंरचना (चतुर्थ चरण) योजना जो दिनांक 30/07/2025 तक पूर्ण होना था, किन्तु उक्त कार्य मात्र 10 प्रतिशत किया गया है, शेष 90 प्रतिशत कार्य आज तक नहीं किया गया है, इसी तरह अन्य निर्माण कार्यों के अपूर्ण होने पर नाराजगी जताई है।

इनका कहना है। सभी संविदाकारो को नोटिस जारी किया गया था जिसमें संविदाकारों द्वारा कार्य को पूर्ण करने का समय मांगा गया है सभी संविदाकारो को पीआईसी द्वारा 31 मई तक कार्य पूर्ण करने का समय दिया गया है। अगर निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं किए जाते हैं तो संविदाकारों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। रामवतार पटेल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी चुरहट।

कार्य अधूरा, भुगतान पूरा

मजे की बात यह है कि नगर परिषद चुरहट क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में चल रहे नाली, सड़क निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत है, कुछ ठेकेदारों द्वारा कार्य भी आरंभ कराया गया, लेकिन कार्य को पूर्ण नहीं किया गया, वहीं विभाग के इंजिनियर द्वारा अधूरे निर्माण कार्यों का मूल्यांकन कर भुगतान किया जा रहा है। इस संबंध का आरोप नगर परिषद चुरहट के रहवासियों ने मीडिया से चर्चा के दौरान लगाया है। यह सत्य है कि चुरहट नगर के विकास में नगर परिषद का अमला सक्रिय नहीं है।

संक्षिप्त समाचार

रेप पीड़ित बच्ची को थाने बुलाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

गुरुग्राम। सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल की बच्ची से रेप के मामले में असंवेदनशील रवैये के लिए हरियाणा पुलिस और बाल कल्याण समिति को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा पीड़ित से मिलने के बजाय उसे थाने बुलाना शर्मनाक है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा- पुलिस अफसरों को देखिए, उनकी पोजिशन देखिए। पुलिस स्टेशन में DCP, ASP रहते हैं। इस अपराध में आपकी यही समझ है तो फिर कानून किसे कहेंगे? यह शॉकिंग है... पुलिस पीड़ित के घर क्यों नहीं जा सकती? क्या वे राजा हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए हरियाणा कैडर की महिला आईपीएस अधिकारियों सहित तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। साथ ही हरियाणा सरकार को विशेष जांच टीम गठित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस को गुरुवार तक मामले के रिकॉर्ड सौंपने के भी आदेश दिए हैं। 4 फरवरी 2026 को एक व्यक्ति ने गुरुग्राम के थाना सेक्टर-53 में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें कहा था- उनकी सोसाइटी की 2 मेड और एक व्यक्ति ने दिसंबर 2025-जनवरी 2026 में उनकी 3 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत और यौन शोषण किया। शिकायत पर पुलिस ने POCSO एक्ट की धारा 6, धारा 17 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(2) (12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार) के तहत केस दर्ज किया। मगर, शुरुआत से ही पुलिस ने मामले में लापरवाही दिखाई। शुरु में दो महिलाओं को डिटेन किया गया, लेकिन तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई। पुरुष आरोपी का नाम भी शुरुआत में FIR में नहीं था।

गुजरात में वकील के जुलूस से कोर्ट की कार्यवाही रुकी, जज ने बाहर आकर कहा- शोर ना करें

भावनगर। गुजरात में भावनगर जिला कोर्ट के बार एसोसिएशन चुनाव के बाद विजयी जुलूस निकाल रहे वकील और डिस्ट्रिक्ट जज के बीच तीखी बहस हो गई। वकील ने जज से यहां तक कह दिया कि आप कौन हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? आप जाकर अपनी कुर्सी संभालिए। इसी दौरान कुछ वकील जज को शांत कराकर कोर्ट रूम में ले गए। यह मामला बुधवार का है। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल हुआ यह है कि स्थानीय वकील अनिरुद्धसिंह झाला लगातार तीसरी बार गुजरात बार एसोसिएशन के सदस्य रूप में चुने गए। कोर्ट परिसर में वे अपने समर्थकों के साथ ढोल-नगाड़े पर नाच रहे थे। तभी डिस्ट्रिक्ट जज एचएस मूलिया की अदालत में सुनवाई चल रही थी। शोर सुनकर वह कोर्ट की कार्यवाही छोड़कर बाहर आ गए। जज ने इस शोर पर आपत्ति जताई तो वकील उन पर भड़क उठे। वकील के खिलाफ कार्रवाई की मांग गुजरात न्यायिक सेवा संघ ने वकील अनिरुद्धसिंह झाला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट और गुजरात बार काउंसिल को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि भावनगर में गुजरात बार काउंसिल चुनाव में विजयी उम्मीदवार अधिवक्ता अनिरुद्धसिंह झाला की विजय यात्रा के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज ने अदालत की कार्यवाही में बाधा डाली गई। इस दौरान अनिरुद्धसिंह झाला ने प्रधान जिला न्यायाधीश के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। गुजरात न्यायिक सेवा संघ ने मांग की है कि गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता अनिरुद्धसिंह झाला के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करे और बार काउंसिल अनिरुद्धसिंह झाला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।

केदारनाथ-बद्रीनाथ में बिना लिमिट के होंगे दर्शन

देहरादून। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि जीएमवीएन के जरिए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। पहले पर्यटन विभाग ने योजना बनाई थी कि पिछले साल की तरह इस बार भी केदारनाथ में रोजाना 18,600 और बद्रीनाथ में 21,600 श्रद्धालुओं की लिमिट रहेगी। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि सामान्य यात्रा में कोई लिमिट लागू नहीं होगी। चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने कैपिंग और टोकन सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मुख्य सचिव को सौंपे गए 11 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया कि यह संख्या सीमा अव्यावहारिक है। श्रद्धालुओं को बेवजह रोका जाता है। सरकार को रोक-टोक के बजाय सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। इस विरोध के बाद सरकार तुरंत हरकत में आई और फैसला बदल दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवहन बेहतर हों। श्रद्धालुओं को समय पर सही जानकारी मिले और किसी को भी असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य के लिए बड़ा अवसर है, इसलिए व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है।

मोहाली में क्लासमेट ने छात्रा का गैंगरेप कराया, फ्रेंडशिप कर प्राइवेट वीडियो बनाए, फिर दोस्त बुलाए

मोहाली। मोहाली के न्यू चंडीगढ़ इलाके में एक 8वीं कक्षा की छात्रा का उसके ही क्लासमेट ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप कर दिया। आरोपियों ने इस वारदात का वीडियो भी बनाया और उसे वॉट्सऐप ग्रुपों में शेयर कर दिया। साथ ही छात्रा को जान से मारने की धमकी दी गई। छात्रा के परिजन की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने चारों मुख्य आरोपियों के साथ पीड़िता की एक नाबालिग सहेली को भी गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपियों में भी 3 नाबालिग हैं। उन्हें अदालत में पेश कर सुधार गृह भेजा गया है। जबकि, एक बालिग आरोपी को 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, 15 वर्षीय छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की वारदात का मुख्य आरोपी पीड़िता का क्लासमेट है। नाबालिग आरोपी क्लासमेट ने पहले पीड़िता के साथ दोस्ती की। फिर उसके कुछ प्राइवेट वीडियो बनाकर उसे डराना शुरू कर दिया। उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता को डराया-धमकाया और अलग-अलग सुनसान जगहों पर ले जाकर छात्रा के साथ कई बार गैंगरेप किया। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पिछले करीब एक महीने से न्यू चंडीगढ़ के अलग-अलग इलाकों में वारदात को अंजाम दिया गया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी. जीवन रेड्डी ने दिया इस्तीफा

हैदराबाद। तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी. जीवन रेड्डी ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी नेताओं द्वारा मनाने के सभी प्रयास विफल रहे। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ-साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की सदस्यता भी छोड़ दी। रेड्डी ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में अपने इस्तीफे के पीछे के कारणों का विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि जगतियाल विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे अन्याय और मानसिक पीड़ा को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया। टी. जीवन रेड्डी ने आरोप लगाया कि उन्होंने विधानसभा और परिषद दोनों में बीआरएस सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन पार्टी में उन्हें अपेक्षित सम्मान और प्राथमिकता नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा कि नामित पद भी दल-बदल कर आए विधायक डॉ. एम. संजय कुमार की सिफारिश पर दिए गए, जिससे वे काफी नाराज थे। रेड्डी की नाराजगी को देखते हुए तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की। प्रदेश अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड और एआईसीसी के सचिव सचिन सावंत ने उनसे मुलाकात कर फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। इससे पहले आईटी मंत्री श्रीधर बाबू भी उनसे मिले थे, लेकिन सभी प्रयास नाकाम रहे। उल्लेखनीय है कि टी. जीवन रेड्डी का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1981 में मल्लियाल पंचायत समिति अध्यक्ष के रूप में की। 1983 में एन. टी. रामाराव के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी से विधायक बने और मंत्री पद संभाला। बाद में मतभेद के चलते 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए। रेड्डी 1989, 1996, 1999, 2004 और 2014 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में वे करीमनगर ग्रेजुएट्स सीट से विधान परिषद सदस्य चुने गए। साथ ही वाई. एस. राजशेखर रेड्डी के मंत्रिमंडल में 2006 से 2009 के बीच कैबिनेट मंत्री भी रहे।

आर्थिक बोझ का हवाला देकर मुआवजा नहीं छीन सकते

यह संवैधानिक अधिकार, जमीन अधिग्रहण मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की याचिका खारिज

एजेंसी, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2019 से पहले हुए भूमि अधिग्रहण मामलों में सोलाटियम और ब्याज देने से जुड़े अपने फैसले पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इससे किसानों और जमीन मालिकों को राहत मिली है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के मामलों में सही मुआवजा मिलना संवैधानिक अधिकार है। इसे कमजोर नहीं किया जा सकता। इसे सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ से नहीं जोड़ा जा सकता। पूरा मामला उन भूमि अधिग्रहण मामलों से जुड़ा है जो 2019 से पहले हुए थे, जिसमें प्रभावित लोगों को सोलाटियम और ब्याज देने का सवाल था। NHAI ने पहले के फैसले को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा।

NHAI ने कहा था- 29 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमीन मालिकों को मिलने वाला ब्याज भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार 9% होगा, न कि NHAI एक्ट के 5% की सीमा के अनुसार। NHAI ने तर्क दिया था कि इससे उस पर करीब 29,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन कोर्ट ने इसे समीक्षा का आधार मानने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी मामलों को दोबारा नहीं खोला जा सकता। यानी 2018 से पहले के बंद मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा, लेकिन जो दावे पहले से लंबित हैं, उन पर कानून के अनुसार फैसला होगा। कोर्ट ने कहा कि जमीन मालिकों के अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया की स्थिरता- दोनों के बीच संतुलन जरूरी है।

क्या है पूरा मामला?: NHAI ने अपनी पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 4 फरवरी 2025 के उस आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तरसेम सिंह (2019) के मुख्य फैसले पर स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी को खारिज कर दिया गया था। 2019 के फैसले में कोर्ट ने NHAI एक्ट की धारा 3J को असंवैधानिक ठहराया था, क्योंकि यह भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को लागू नहीं होने देती थी और इससे समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन होता था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 1997 (जब धारा 3J लागू हुई) से लेकर 2015 (जब 2013 का भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन कानून राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण पर लागू हुआ) के बीच जिन जमीन मालिकों की जमीन अधिग्रहित हुई, वे भी उसी तरह के लाभ पाने के हकदार हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अन्य मामलों में दिए जाते हैं।

ममता बोलीं- बीजेपी बंगाल को खत्म करना चाहती है

एजेंसी, नई दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई

◆ एसआईआर में बंगालियों के नाम काट दिए

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मैनागुड़ी में एक रैली में कहा कि भाजपा बंगाल राज्य को ही खत्म करना चाहते हैं। बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी है। आपको बिहार में मिला दिया जाएगा। मैंने नॉर्थ बंगाल का बंटवारा रोक दिया है। यह कुछ दिन पहले ही सोशल नेटवर्क पर सामने आया था, और मैंने उसी दिन अपनी आवाज उठाई थी। उन्होंने आगे कहा कि असली मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। साथ ही, पहचान और नागरिकता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसे एक वैध भारतीय मतदाता के तौर पर मान्यता दी जा रही है और किस आधार पर? उधर, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 के लिए AIADMK ने अपने गठबंधन (NDA) के साथ सीट शेयर घोषित कर दिया है। कुल 234 सीटों में से AIADMK 169 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं, सहयोगी दलों के लिए 65 सीटें दी हैं। यह प्रदर्शन तिरुवैयार विधानसभा क्षेत्र के तिरुक्कट्टुपल्ली कडावेदी इलाके में हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने NDA गठबंधन में AMMK को सीट दिए जाने का विरोध जताया।

चेन्नई के मायलापुर विधानसभा क्षेत्र में AIADMK महासचिव ईडप्पादी के. पलानीस्वामी ने BJP नेता तमिलिसाई सुंदरराजन के साथ चुनावी रैली की। इस दौरान दोनों नेताओं ने गठबंधन (NDA) के समर्थन में प्रचार किया और लोगों से वोट देने की अपील की। रैली में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे, जहां नेताओं ने सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को लोगों के सामने रखा और विपक्ष पर भी निशाना साधा।

48 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्नों की गिनती शुरू

एजेंसी, पुरी

पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार (खजाने) की गिनती और लिस्ट बनाने की प्रक्रिया 48 साल बाद बुधवार से शुरू हो गई। 'रत्न भंडार' भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषणों का खजाना है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के अनुसार यह काम तय शुभ समय (दोपहर 12:09 से 1:45 बजे के बीच) में शुरू किया गया। इसमें केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश दिया गया। इस प्रक्रिया से मंदिर की हर दिन की पूजा-पाठ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। श्रद्धालुओं को बाहर के बैरिकेड (बाहर कथा) से दर्शन की अनुमति है, जबकि अंदर वाले हिस्से (भीतर कथा) में इस दौरान प्रवेश बंद रखा गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति के बनाए गए नियमों के अनुसार, पहले रोज इस्तेमाल होने वाले गहनों की गिनती होगी, फिर रत्न भंडार के बाहरी कक्ष और अंत में अंदरूनी कक्ष को खोला जाएगा।

1978 में हुई थी गिनती: इससे पहले 13 मई से 23 जुलाई 1978 में हुई गिनती में 454 सोने-मिश्रित वस्तुएं (128.38 किलो), 293 चांदी की वस्तुएं (221.53 किलो) और कई कीमती रत्न दर्ज किए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि इस बार आधुनिक तकनीक की मदद से यह काम जल्दी पूरा किया जाएगा। दो रत्न विशेषज्ञ (जेमोलॉजिस्ट) पहचान में मदद कर रहे हैं और हर वस्तु की डिजिटल फोटो ली जा रही है। सोने के गहनों को पीले कपड़े में, चांदी को सफेद कपड़े में और अन्य वस्तुओं को लाल कपड़े में लपेटकर छह खास बक्सों में रखा जा रहा है।

रूस ने यूक्रेन पर दागे 1000 से ज्यादा ड्रोन व मिसाइलें, सात लोगों की मौत

एजेंसी, मास्को

रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले को अंजाम देते हुए करीब 1,000 ड्रोन और मिसाइलें दागीं। इस हमले में कई लोगों की मौत हुई, दर्जनों घायल हुए और ल्वीव समेत कई शहरों में भारी तबाही देखने को मिली। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब युद्ध खत्म करने की कोशिशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार यूक्रेन पर रूस ने हाल के दिनों में अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया है। अधिकारियों के अनुसार करीब 24 घंटे के भीतर रूस ने लगभग 1,000 ड्रोन और मिसाइलें दागीं, जिनमें कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बताया गया है कि रात के समय करीब 400 लंबी दूरी के ड्रोन और 23 क्रूज मिसाइलें दागी गईं। इसके बाद दिन में भी असामान्य रूप से 556 ड्रोन से हमला किया गया, जिसने पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया।

पश्चिमी शहर ल्वीव में एक रूसी ड्रोन ने 16वीं सदी के बर्नार्डिन मठ (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) को नुकसान पहुंचा है। हमले में पास की आवासीय इमारतों में आग लग गई और कई लोग घायल हो गए। यूक्रेनी के अनुसार टेरनोपिल, विन्नित्सिया, इवानो-फ्रैंकिव्स्क, ज़ाइटॉमिर, ज़ापोरिज़्या और डीनिप्रो सहित कई क्षेत्रों में हमले हुए। इवानो-फ्रैंकिव्स्क में दो लोगों और विन्नित्सिया में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके अलावा पोल्टावा क्षेत्र में दो लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। वहीं, जापोरिज़्या में एक की मौत और पांच घायल तथा खार्किव क्षेत्र में एक ट्रेन पर हमले में 61 वर्षीय यात्री की मौत हो गई।

यूक्रेन की वायु सेना का दावा है कि उसने दिन के समय दागे गए 556 ड्रोन में से अधिकांश को नष्ट या निष्क्रिय कर दिया। फिर भी हमलों का असर व्यापक रहा और 11 प्रशासनिक क्षेत्रों में नुकसान की पुष्टि हुई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस हमले का पैमाना दिखाता है कि रूस का युद्ध खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की।

डॉ. कल्याणी सिंह के पत्र पर पल्लवी प्रकरण में प्रशासन सक्रिय, न्याय की दिशा में बढ़ते कदम

लोकतंत्र की शान

धर्मशाला/हिमाचल प्रदेश: धर्मशाला स्थित एक कॉलेज में छात्रा पल्लवी की मृत्यु से जुड़े अत्यंत संवेदनशील प्रकरण में अब प्रशासनिक स्तर पर सकारात्मक पहल देखने को मिल रही है। इस मामले को प्रमुखता से उठाने वाली डॉ. कल्याणी सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन ने हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। डॉ. कल्याणी सिंह ने बताया कि उन्होंने इस गंभीर विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री एवं पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। उनके इस प्रयास के बाद प्रशासन की ओर से ईमेल के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि मामले की जांच विधिसम्मत और पारदर्शी तरीके से जारी है, तथा हर पहलू पर गहनता से कार्य किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस ने आवश्यक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। परिजनों, सहपाठियों और कॉलेज प्रशासन से पूछताछ के साथ-साथ तकनीकी साक्ष्यों की भी गंभीरता से जांच की जा रही है। यह सभी कदम इस बात का संकेत हैं कि प्रशासन इस मामले को पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ देख रहा है। डॉ. कल्याणी सिंह ने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाना केवल प्रशासन का दायित्व नहीं, बल्कि समाज के हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की तत्परता ही न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास मजबूत करती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे भविष्य में भी हर अन्याय, उत्पीड़न और अपराध के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रहेंगी। उनका दृढ़ संकल्प है कि जब तक इस मामले में सभी दोषियों को सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक न्याय की यह लड़ाई जारी रहेगी। डॉ. कल्याणी सिंह ने कहा, "जब तक समाज में अन्याय और अत्याचार होते रहेंगे, तब तक हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि हम निडर होकर सच्चाई के साथ खड़े रहें और पीड़ितों की आवाज बनें,अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्ची सामाजिक जिम्मेदारी है।

ईरान ने इजराइल पर दागीं मिसाइलें, कठोर लहजे में ट्रंप से बातचीत का दावा खारिज

एजेंसी, तेहरान/इजराइल

अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। 28 फरवरी से आसमान से मौत बरस रही है। स्थिति और खराब होने का खतरा है। ईरान के सर्वोच्च सैन्य निकाय खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने आज कठोर लहजे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत के दावे को खारिज कर दिया। निकाय ने कहा कि युद्ध नहीं रुकेगा। उधर, ईरान ने आज इजराइल पर जोरदार हवाई हमला किया है।

ईरान के प्रेस टीवी, मेहर न्यूज एजेंसी, तसनीम न्यूज एजेंसी, अल जजीरा चैनल और द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार की रिपोर्ट्स के अनुसार सर्वोच्च सैन्य निकाय ने अब से कुछ देर पहले साफ कर दिया है कि ट्रंप का बातचीत का दावा बिलकुल बेमानी है। उसमें कोई दम नहीं है। ईरान आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़कर अंजाम तक पहुंचाएगा। ईरानी सेना के इस रुख से पहले इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने इजराइल में ऑपरेशन 'ट्रू प्रॉमिस 4' की 80वीं लहर को अंजाम दिया है। इस लहर के दौरान इजराइल के उत्तरी हिस्से में मौजूद रणनीतिक ठिकानों और सैन्य केंद्रों पर हमला किया गया है। साथ ही पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी चौकियों पर भी जोरदार प्रहार किया है। आईआरजीसी ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि यह हमला लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हमलों के प्रतिरोध में किया गया है। इजराइल के उत्तरी शहर सफेद में सैन्य कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। आईआरजीसी ने कहा कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज के उत्तरी जमावड़े वाले ठिकानों और गाजा पट्टी पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाएंगे। तेल अवीव, किर्यात शमोना और बेनी बराक के अलावा कुवैत में अली अल-सलेम और आरिफजान, जॉर्डन में अल-अजराक, और बहरीन में शेख ईसा स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं।

अमेरिका में गृह सुरक्षा विभाग की बजट फंडिंग और सीमा सुरक्षा पर खींचतान जारी

एजेंसी, वाशिंगटन

अमेरिका में बजट फंडिंग और सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बीच खींचतान जारी है। सीनेट डेमोक्रेट्स ने मंगलवार को कहा कि वे गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) को फिर से खोलने (बजट फंडिंग) के लिए किसी भी समझौते के हिस्से के तौर पर, आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) में सुधारों के लिए जोर देते रहेंगे। इससे फंडिंग की रुकावट का कोई हल निकालने की रिपब्लिकन पार्टी की कोशिशें और मुश्किल हो गई हैं। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सीनेट में अल्पमत दल के नेता और न्यूयॉर्क के सीनेटर चक शूमर ने यूएस कैपिटल में संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हमें आईसीई पर लगाम लगानी होगी और हिंसा रोकनी होगी। हमें सुधारों की जरूरत है।" इससे पहले सोमवार देर रात बातचीत में एक बड़ी सफलता मिलने के बाद सीनेट रिपब्लिकंस ने मंगलवार को डेमोक्रेट्स को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा। रिपब्लिकंस के एक समूह ने सोमवार शाम को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की और एक संभावित समझौते को लेकर आशावादी होकर कैपिटल लौटे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास कोई हल है तो अलबामा की सीनेटर केटी ब्रिट ने कहा, "हां, हमारे पास है।"

लेकिन मंगलवार दोपहर को एक अहम बैठक के बाद डेमोक्रेट्स ने इस प्रस्ताव पर पानी फेर दिया और आईसीई में सुधारों की अपनी मांगों को दोहराया। जनवरी में मिनियापोलिस में फ़ेडरल एजेंट्स की गोलीबारी की घटनाओं के बाद डेमोक्रेट्स ने सुधारों के बिना इस एजेंसी को फंड देने से इनकार कर दिया है। शूमर ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के प्रस्ताव में इमिग्रेशन एजेंसी के लिए कोई सुधार शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत अभी भी जारी है और हम उन्हें अपना प्रस्ताव वापस भेजेंगे।

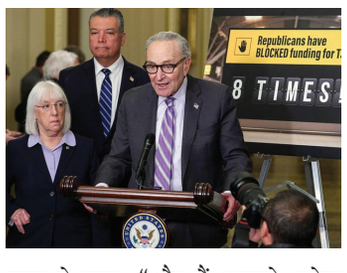

शूमर ने कहा, "और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि इसमें काफी अहम सुधार शामिल होंगे।" साउथ डकोटा के रिपब्लिकन सीनेट मेजोरिटी लीडर जॉन थून ने पत्रकारों को बताया कि रिपब्लिकन पार्टी का प्रस्ताव डीएचएस के बजट का 94 प्रतिशत हिस्सा फंड करेगा। आईसीई की डिपोर्टेशन विंग (एनफोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस) के लिए 5.5 बिलियन डॉलर सुरक्षित रखा जाएगा। थून ने मंगलवार को कहा कि "कई सुधार आईसीई की फंडिंग पर निर्भर हैं।"

सीनेट में डेमोक्रेट्स की तरफ से फंडिंग मामलों की प्रमुख वाशिंगटन की सीनेटर पैटी मरे ने साफ कर दिया कि डेमोक्रेट्स मामूली सुधारों के लिए लगातार जोर डाल रहे हैं। उनकी मुख्य शर्त यह है कि सुधारों को कानून का रूप जरूर मिलना चाहिए। उधर, हाल के हफ्तों में डेमोक्रेट्स और व्हाइट हाउस के बीच प्रस्तावों का आदान-प्रदान होता रहा है। पिछले हफ्ते सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने सीमा मामलों के प्रमुख (बॉर्डर जार) टॉम होमन से दो बार मुलाकात की। यह सब इस गतिरोध को खत्म करने के बढ़ते दबाव के बीच हुआ। मरे ने कहा कि आईसीई सुधारों के लिए जोर डालते हुए उनकी और सीनेट के अन्य डेमोक्रेट्स की व्हाइट हाउस के साथ सार्थक बैठकें हुई हैं। ये बैठकें तब और भी ज्यादा सार्थक होतीं, अगर राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर लगातार नई और बेतुकी मांगें न करते।" उन्होंने कहा, "रिपब्लिकन के साथ किसी बात पर आम सहमति बनाना बहुत मुश्किल होता है, जब यह साफ ही न हो कि उनके अपने ही लोगों के बीच कोई आम सहमति है या नहीं।" राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को डीएचएस की फंडिंग पर चल रही बातचीत में तब अड़चन डाल दी, जब उन्होंने रिपब्लिकन से कहा कि वे कोई समझौता न करें। उन्होंने तर्क दिया कि सांसदों को डीएचएस की फंडिंग को ' सेव अमेरिका एक्ट ' से जोड़ देना चाहिए। राष्ट्रपति पिछले कई हफ्तों से सांसदों पर इस चुनाव विधेयक को मंजूरी देने का दबाव डाल रहे हैं। इस विधेयक के तहत, मतदान पंजीकरण कराने के लिए नागरिकता का प्रमाण देना जरूरी होगा, और वोट डालने के लिए फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। डेमोक्रेट्स इस विधेयक का कड़ा विरोध कर रहे हैं। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में कहा कि डेमोक्रेट्स ने समझौते को तोड़ दिया है।

ईरान-इज़रायल-अमेरिका युद्ध- जीवन से जुड़े बुनियादी ढांचे बिजली, पानी ऊर्जा और आम नागरिकों पर मंडराता वैश्विक संकट-समग्र विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

» वैश्विक ऊर्जा इमरजेंसी- तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में ही दुनियाँ पर पड़ा असर-जंग का बदलता चेहरा-नेताओं के दावों से जनता की पीड़ा तक

» युद्ध संकट ने जीवन की बुनियादी जरूरतों रसोई गैस, परिवहन, बिजली और पानी को सीधे प्रभावित- सामाजिक असंतोष, आर्थिक अस्थिरता बढ़ने का ख़तराबढ़ा -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया – वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष,विशेषकर ईरान,इज़रायल और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात ने विश्व व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा और तत्काल प्रभाव ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ा है।अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के अनुसार, यह संकट 1970 के दशक के तेल संकट के बाद सबसे गंभीर हो सकता है। कई देशों ने बिजली और ईंधन की खपत कोनियंत्रित करने के लिए ऊर्जा इमरजेंसी जैसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।पाकिस्तान,बांग्लादेश, श्रीलंका फिलीस्तीन जैसे देशों में बिजली कटौती,पेट्रोल-डीजल की सीमित आपूर्ति और स्कूल बंद करने जैसे निर्णय लिए जा रहे हैं।आश्चर्यजनक रूप से, यह संकट केवल विकासशील देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप और न्यूजीलैंड जैसे विकसित क्षेत्रों में भी ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहता हूं कि हर युद्ध की शुरुआत में इसे इंसानियत की रक्षा और शांति की स्थापना के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है।जब ऊर्जा से आगे बढ़कर पानी बना युद्ध का नया हथियार तो यह इस युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू है।अब यह केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पानी जैसे जीवनदायी संसाधन तक पहुंच गया है।खाड़ी देशों में प्राकृतिक मीठे पानी की भारी कमी है और वे समुद्री पानी को शुद्ध करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर हैं।यदि इन संयंत्रों पर हमले होते हैं, तो स्थिति भयावह हो सकती है। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब अपनी लगभग 70 प्रतिशत पेयजल आवश्यकता इन प्लांट्स से पूरी करता है, जबकि कुवैत लगभग 90 प्रतिशत और ओमान 86 प्रतिशत तक निर्भर है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने या संयंत्रों के नष्ट होने पर इन देशों में पानी का संकट तुरंत उत्पन्न हो सकता है।ट्रंप ने भी दावा किया कि यह अभियान ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने और वहां के लोगों को तानाशाही शासन से मुक्ति दिलाने के लिए है।दूसरी ओर, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इज़रायल और पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी।लेकिन 26 दिनों के भीतर ही इस युद्ध का स्वरूप बदल गया है।अब सैन्य ठिकानों की बजाय आम नागरिकों के जीवन से जुड़े बुनियादी ढांचे बिजली,पानी और ऊर्जा पर हमले की धमकियां दी जा रही हैं। ट्रंप द्वारा 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की चेतावनीदी थीं और उसके जवाब में ईरान द्वारा पूरे खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा एवं जल ढांचे को नष्ट करने की धमकी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब युद्ध का केंद्र जनता बन चुकी है। साथियों बात अगर हम डिसैलिनेशन प्लांट्स पर खतराः जीवनरेखा पर सीधा हमला इसको समझने की करें तो ईरान द्वारा खाड़ी देशों के प्रमुख जल और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने की धमकी ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन जैसे देशों के प्रमुख प्लांट्स खतरे में हैंयदि ये संयंत्र नष्ट होते हैं, तो न केवल पीने के पानी की आपूर्ति ठप हो जाएगी, बल्कि बिजली उत्पादन भी प्रभावित होगा, क्योंकि ये दोनों प्रणालियां आपस में जुड़ी हुई हैं। इस स्थिति में पूरा खाड़ी क्षेत्र प्यास और अंधेरेके संकट में फंस सकता है। साथियों बात अगर हम आम नागरिकों पर असरःमानवीय जीवन से जुड़े बुनियादी ढांचे बिजली,पानी ऊर्जा और आम नागरिकों पर मंडराता वैश्विक संकट जीवनशैली में भारी बदलाव इसको समझने की करें तो इस युद्ध का सबसे बड़ा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कई देशों में ईंधन की कमी के कारण स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कंपनियां वर्क फ्रॉम होम लागू कर रही हैं, और पेट्रोल-डीजल की खरीद पर सीमाएं तय की जा रही हैं। बिजली कटौती आम हो गई है, जिससे उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहे हैं।ऊर्जा संकट ने

जीवन की बुनियादी जरूरतों रसोई गैस, परिवहन, बिजली और पानी को सीधे प्रभावित किया है। इससे सामाजिक असंतोष और आर्थिक अस्थिरता बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है ठीक वैसे ही,वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतराः मंदी की आशंका ऊर्जा संकट का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ती है,जिससे महंगाई बढ़ती है और उपभोक्ता खर्च घटता है।विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, जहां बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। इस युद्ध के कारण लाखों भारतीयों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है, और हजारों लोग वापस लौट चुके हैं। साथियों बात कर हम पानी की जंगःभविष्य का सबसे बड़ा खतरा इसको समझने की करें तोविश्लेषकों का मानना है कि यह संघर्ष भविष्य में "पानी की जंग" का संकेत हो सकता है। जिस तरह तेल ने 20वीं सदी में भू-राजनीति को प्रभावित किया, उसी तरह पानी 21वीं सदी का सबसे बड़ा संसाधन बन सकता है।यदि जल स्त्रोतों और जल आपूर्ति प्रणालियों पर हमले बढ़ते हैं, तो यह मानव अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन जाएगा। पानी की कमी न केवल स्वास्थ्य संकट पैदा करेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर पलायन, सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म दे सकती है। साथियों बात अगर हम ऊर्जा संकट का वैश्विक विस्तारः 1973 जैसा खतरा इसको समझने की करें तो,मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरह प्रभावित किया है। मध्य पूर्व विश्व के तेल और गैस उत्पादन का केंद्र है, जहां से बड़ी मात्रा में ऊर्जा संसाधन पूरी दुनिया में निर्यात होते हैं। कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के उत्पादन केंद्रों पर खतरे के कारण तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल आया है।यह स्थिति 1973 के तेल संकट की याद दिलाती है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा था। आज भी वही खतरा मंडरा रहा है,ऊर्जा की कमी,महंगाई में वृद्धि,और वैश्विक मंदी का जोखिम मंडरा रहा है। साथियों बात अगर हम होर्मुज जलडमरूमध्यः वैश्विक आपूर्ति की जीवनरेखा पर संकट,होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है,जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव और हमलों के कारण तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे आपूर्ति बाधित हो रही है।भारत सहित एशिया की कई अर्थव्यवस्थाएं, जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, इस संकट से सीधे प्रभावित हो रही हैं। भारत में ईंधन की कीमतों में वृद्धि, महंगाई और आर्थिक दबाव के रूप में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। साथियों बाद अगर हम युद्ध के बयानों पर नजर डालें तोहर जंग की शुरुआत में एक घोषणा की जाती है- यह जंग इंसानियत को बचाने की जंग है, लाखों जान बचाने के लिए न टाली जा सकने वाली जंग है. ईरान के खिलाफ 26 दिन पहले अमेरिका और इजरायल की तरफ से जब जंग शुरू की गई थी तब भी कुछ ऐसे ही दावे किए गए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो ईरान के लोगों को एक तानाशाही शासन से आजादी दिलाने निकले हैं, इस्लामिक शासन को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए निकले हैं. ईरान ने भी जवाबी हमला करते हुए कहा कि वह इजरालय और मीडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा,हालांकि अब कहानी का प्लॉट ही बदल चुका है।अब नेता नहीं जनता निशाने पर है. ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि उनकी सेना पूरे ईरान के बिजली संयंत्र को निशाने बनाने वाली है, तो वहीं ईरान ने कहा कि कोई भी हमला हुआ तो वह पूरे खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा और जल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा.ईरान के पावर प्लांट तबाह कर देंगे। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि युद्ध का असली चेहरा और मानवता के लिए चेतावनी,ईरान, इज़रायल और अमेरिका के बीच बढ़ता संघर्ष अब केवल सैन्य टकराव नहीं रह गया है, बल्कि यह ऊर्जा, पानी और मानव अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है।इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युद्धों में सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को होता है। बिजली, पानी और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतें जब युद्ध का हथियार बन जाती हैं, तो यह मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाता है।दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां अगर समय रहते कूटनीतिक समाधान नहीं निकाला गया, तो यह संकट वैश्विक आपदा का रूप ले सकता है। यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए एक चेतावनी है कि संसाधनों की लड़ाई भविष्य में कितनी भयावह हो सकती है।

-संकलनकर्ता लेखक
- क्रर विशेषज्ञ स्तंभकार
साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक
चिंतक कवि संगीत माध्यमा
सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन
सनमुखदास भावनानी गोंदिया
महाराष्ट्र 9284141425

चूड़ियाँः कायरता नहीं साहस का प्रतीक - देवी से हम तक

लेखिका - निमिषा सिंह

चैती नवरात्रि, माँ दुर्गा की उपासना का अवसर जिसमे माता रानी की विशेष पूजा के साथ उनके सोलह श्रृंगार का भी विधान है। अष्टमी/नवमी की की खरीदारी करने के क्रम में मेरी नजर मां दुर्गा के लिए सजाई जा रही मनमोहक चूड़ियों पर पड़ी। सुर्ख लाल,चमकती हुई कांच की ये चूड़ियां जैसे सीधे देवी के श्रृंगार का हिस्सा बनकर मेरे सामने खिल उठीं। जब भी चूड़ियां देखती या पहनती हूं भाषाई सभ्यता को लेकर मेरे मन में हमेशा से एक तर्क चलता रहा है। हाल ही में प्रकाशित हुई एक खबर जिसमे यूजीसी नियमों के विरोध में लखनऊ सवर्ण मोर्चा द्वारा भाजपा नेताओं के घर के आगे चूड़ियां और बिंदिया रखी गई। इस खबर ने फिर से मन को व्यथित कर दिया और सोचने और इस विषय पर लिखने के लिए विवश कर दिया कि प्रतीकात्मक हिंसा और लैंगिक पूर्वाग्रह हमारे समाज में कितनी गहरी जड़ें जमा चुके हैं। पितृसत्तात्मक सोच में महिला की स्वतंत्रता और शक्ति को सीमित करने की प्रवृत्ति रही है लिहाजा पुरुषवादी दृष्टिकोण ने यह मान लिया कि मर्दानगी केवल कठोरता में निहित है और कोमलता कमजोरी है। जो आज भी बे रोकटोक प्रचलन में है। वैचारिक मतभेद हो या व्यक्तिगत टकराव जब-तब पुरुषों को चूड़ियां भेंट करने की ख़बरें आती रहतीं हैं। मानो चूड़ियां ना हुई रण निमंत्रण हो गई। बचपन से ही हमे यह बताया गया कि चूड़ियां नारी के श्रृंगार सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक हैं किंतु हमे यह नही बताया गया कि चूड़ियां अक्सर पुरुषत्व की प्रेरणा और चुनौती भी बन जाती हैं । मुझे यह समझ नहीं आता कि पुरुषवादी दृष्टिकोण साबित करने के लिए चूड़ियां ही क्यों फेंकीं जाती हैं? चूड़ियां किस बात का प्रतीक हैं? कमजोरी का? कायरता का? बचपन से ये डायलॉग सुनते आ रहे हैं कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखीं हैं या फिर औरतों की तरह चूड़ियां पहनकर घर पर बैठो और मजे की बात यह है कि किसी को चूड़ियों के इस तरह के इस्तेमाल पर ऐतराज भी नहीं है। होगा भी क्यों? सोचेंगे तो होगा ना। जरा सोचिए अपने विरोधी को चूड़ी देकर आप उसकी नही बल्कि महिला शक्ति का अपमान करते है। चूड़ियां तो मां काली और दुर्गा के हाथ में भी होती हैं तो क्या उनसे बढ़कर है कोई शक्ति का रूप? चूड़ियां तो हर उस लडक़ी के हाथ में होती हैं जो नए सपने सजाती है और बड़ी ही मजबूती से अपने माता-पिता के घर को छोडक़र एक नए घर और अंजान लोगों को अपनाती है। चूड़ियां तो उन हाथों में भी होती हैं जो नौ महीने तक एक जीवन को अपने अंदर पालती हैं और दर्द की चरम सीमा को पार करके एक नए जीवन को दुनिया में लाती हैं। चूड़ियां तो उन हाथों में भी थी जिन्होंने महाकाव्य लिख डाले। चंद्रयान 2 के परीक्षण के दौरान हम सब ने नासा की महिला वैज्ञानिकों के हाथों में मौजूद चूड़ियों को तो देखा ही होगा। भरी दुपहरी में कमर में बच्चे को बांधकर ईट के भट्टों पर काम कर रही उस मां के हाथों में भी मैने चूड़ियां देखी है। कहीं से भी कमजोर तो नही दिखी वो मुझे। आज हर उस पुरुष से मेरा एक सवाल है जो अपनी भाषा में चूड़ियों का बेजा प्रयोग करते है। ऐसा कौन-सा रूप देख लिया आप सब ने हमारा कि हमारे श्रृंगार को कमजोरी या नकारेपन का प्रतीक बना दिया गया। कई बार तो ये सोच ही मुझे पल्ले नहीं पड़ती कि अगर किसी का अपमान करना है तो उसे बताया जाए कि वो औरत के समान है क्योंकि औरत मतलब कमजोर। औरत मतलब नाकारा। सदियों से यह मानसिकता और ऐसी महिला विरोधी टिप्पणियां प्रचलन में हैं और हम आज भी यूं ही इसे हांकते चले आ रहे हैं। इतना होने के बावजूद अगर कोई यह कहे कि ऐसा नहीं है। यह औरतों का अपमान नहीं है। उनसे मैं जरूर जानना चाहूंगी कि कैसे नहीं है? चूड़ियां हम महिलाओं का श्रृंगार हैं। पौराणिक धार्मिक या सांस्कारिक जो भी कारण हो सच यही है की हम औरतें अपने पति की मंगलकामना के लिए ही इन्हें पहनती हैं। कई बार हाथों में चुभता भी है। कभी टूट जाएं तो चोट भी लग जाती है पर फिर भी हम इसे पहनती हैं। जब मैं छोटी थी और मैंने कई बार घर में अपनी मां को देखा कि बर्तन धोते वक्त उनकी चूड़ियां टूट कर चुभ जातीं थीं और खून निकलने लगता। मैंने कई बार पूछा उनसे आप इसे क्यों पहनती हैं उतार फेंको इसे। वह गुस्से से लाल हो जातीं और कहती इस तरह के सवाल दोबारा मत पूछना। अब समझ में आता है कि नारी को सहनशील और त्याग जैसे विशेषणों से क्यों नवाजा गया है। चूड़ियां पहनना कोई इतना आसान काम नहीं है जितना कि आप पुरुष सोचते हैं।

धार्मिक स्थलों को क्यों नही मिलती बंदरों से मुक्ति

अशोक मधुप वरिष्ठ पत्रकार

धार्मिक स्थलों को बंदरों से क्यों नही मिलती मुक्ति। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि इन स्थानों पर आने वाले श्रद्धालु कब तक इनके आंतक झेलते रहेंगे? कब तक इनका शिकार होते रहेंगे? हाल में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु अपने कार्यकाल में 19 मार्च को वृंदावन आईं। वे दूसरी बार यहां आईं है। इससे पहले इसी पद पर रहते हुए प्रणब मुखर्जी व रामनाथ कोविंद भी अपने कार्यकाल में दो बार वृंदावन आए थे। लेकिन, राष्ट्रपति मुर्मु वृंदावन के तीन दिवसीय प्रवास पर आने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्रप्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह एक बार वृंदावन आए। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, आर वेंकटरामन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी वृंदावन अपनी धार्मिक यात्रा पर आ चुके हैं। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी दो बार वृंदावन आए। आश्रय सदन में वृद्ध विधवा माताओं से मुलाकात करने आए थे। राष्ट्रपति पद पर रहते प्रणब मुखर्जी पहली बार 16 नवंबर 2014 को अक्षयपात्र में चंद्रोदय मंदिर के भूमि पूजन में आए तो दूसरी बार 18 नवंबर 2015 को चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमनोत्सव के पांच सौ वे वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में आए थे। राष्ट्रपति पद पर रहते ज्ञानी जैल सिंह 1987 में वृंदावन आए और रंगजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे 1957 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्रप्रसाद वृंदावन आए। उप राष्ट्रपति पद पर रहते 1985 में आर वेंकटरामन, 1993 में डॉ. शंकरदयाल शर्मा, 1959 में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन वृंदावन आ चुके हैं। राष्ट्रपति या कोई वीवीआईपी जब भी वृंदावन आता है। प्रत्येक बार उनकी सुरक्षा तो होती ही है। सबसे बड़ा काम होता है वीवीआईपी को यहां के झपटमार बदंर से बचाना। ये बंदर झपटामार कर श्रद्धालु का चश्मा उतारते और किसी ऊंची जगह पेड़ या दीवार पर जाकर बैठ जाते हैं। ये चश्मा तभी लौटाते हैं जब उन्हें खाने के लिए फ्रुटी, केला या दूसरे खाने के सामान दिए जाएं। वीवीआईपी दौरे को देखते हुए प्रशासन लंगूरों के जगह- जगह कट आउट लगवाता है। माना जाता है कि लंगूर से बंदर डरतें हैं।उन्हें डराने के लिए ऐसा किया जाता है। कुछ जगह लंगूर भी लाकर बांध दिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु की सुरक्षा से लेकर रूट पर व्यवस्थाओं को दुरस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने रात दिन एक कर दिया। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के दौरे को देखते एक प्रशासन ने लंगूरों के जगह- जगह कट आउट लगवाए।

लेखक को चित्रकूट में हनुमान गढ़ी जाने का अवसर मिला। वहां रास्ते में बंदर और लंगूर मिलते और आपके कपड़े और बैग पकड़कर रोक लेते हैं। वे आपके बैग और जेब से खाने का सामान प्रसाद आदि निकालकर ही आपको आगे जाने देते हैं। शुक्रताल में तो हनुमान धाम में बंदरों को भगाने के लिए लंगूर बांधा हुआ था। बंदर उसके अभयस्त हो गए थे। उन्हें पता था कि रस्सी में बंधे लंगूर की पंहुच कहां तक हैं। बदंर आते और लंगूर की पंहुच की दूरी से अगल रहकर लौट जाते। प्रश्न है कि वीवीआइपी के आने पर ही क्यों बंदरों को रोकने की व्यवस्था होती है। देश के आम आदमी को भी वीवीआईपी क्यों नही समझा जाता। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। उसके लिए क्यों नही ऐसी व्यवस्थाएं होती। बंदर हम हिंदुओं की श्रद्धा है। हम उसे पवित्र मानते हैं। पूजनीय मानते है। इतना होने पर भी उसके भोजन की व्यवस्था क्यों नही करते। अयोध्या में बड़ी तादाद में बंदर है। हनुमान गढ़ी पर मैंने बंदरों को फूलों की माला तोड़कर उसमें भोजन के अंश तलाशते देखा है। इसी शहर में डस्टविन से भोजन खोजते बंदर मुझे मिलें हैं। हमारी समाज सेवी संस्थाए क्यों नही इनके भोजन की जरूरत पूरी करती। बंदरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढती बंदरों की जनसंख्या को भोजन चाहिए। भोजन ने मिलने वह निरीह प्राणी अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करेगा। बंदरों के आतंक के कारण कई शहरों में तो महिलाओं और बच्चों का छतों पर जाना कठिन हो गया है। शहरों की नही अब तो जंगल में भी इनकी बढ़ती आबादी किसानों के लिए संकट बन चुकी है। भोजन के अभाव में बंदर खेतों की फसल तोड़कर खा रहे हैं। गेंहू की बाली खा जाते है। बोए गए गन्ने के बीज जमीन से निकाल कर वे अपनी उदरपूर्ति कर रहे हैं। किसान फसल की रक्षा को लेकर परेशान हैं।अब तो किसानों ने खेतों की रक्षा के लिए नौकर रखने शुरू कर दिए हैं। आज बंदरों का आंतक धार्मिक स्थलों के साथ अन्य स्थानों पर भी बढ़ता जा रहा है। शहरी आबादी के साथ किसान भी परेशान है। आज जरूरी हो गया है कि सरकार द्वारा बंदरों की आबादी कम करने के लिए अभियान चलाया जाए। बंदरों के ग्रुप लीडर की नसंबदी कराकर उनकी आबादी नियंत्रित की जाए। जनता के शोर मचाने पर बंदरों का पकड़कर जंगलों में छोड़ा जाना कोई स्थायी निदान नही है। ये जंगल और वनों से लौटकर फिर आबादी की ओर आ जाते हैं। बढ़ती बंदरों की आबादी को भोजन चाहिए। भोजन न मिलने पर उन्हें भी पेट भरना है। जैसे आदमी अपनी भोजन की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे साधन ढूंढ़ता है। वैसे ही आज बंदर कर रहे हैं। तीर्थ स्थलों पर चश्मा छीन रहे हैं तो कुछ जगह श्रद्धालुओं को पकड़कर उनके बैग से भोजन ले रहे हैं। गांव और शहरों में भोजन के लिए कपड़े उठाकर ले जाना आम बात है। ये उठाए गए कपड़े तब छोड़ते हैं, जब उन्हें खाने की सामग्री मिल जाए।

अशोक मधुप
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

सेना का बड़ाईरानी ऐलानः "पूरी जीत तक जारी रहेगी कार्रवाई, हर चुनौती का देंगे जवाब"

लोकतंत्र की शान

ईरान की सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ कमांडर जनरल अब्दुल्लाही ने मौजूदा हालात को बेहद संवेदनशील बताते हुए साफ शब्दों में कहा है कि देश की सेना अपनी सैन्य कार्रवाई तब तक जारी रखेगी, जब तक पूरी तरह से जीत हासिल नहीं हो जाती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं अपने सर्वोच्च नेतृत्व के आदेशों का पूरी निष्ठा के साथ पालन कर रही हैं और देश की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर तैयार हैं। रिपोर्ट के अनुसार, Pars Today से बातचीत में जनरल अब्दुल्लाही, जो ख़ातमुल अंबिया हेडक्वाटर के कमांडर हैं, ने अंतरराष्ट्रीय हालात पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से United States की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका ने कई दशकों तक दुनिया की कमजोर और मजलूम क़ौमों—खासतौर पर इस्लामी देशों—पर दबाव बनाकर उनका शोषण किया है। जनरल अब्दुल्लाही ने कहा कि अब वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं और दुनिया यह देख रही है कि इन तथाकथित महाशक्तियों की पकड़ धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि Iran ने दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ इन दबावों का सामना किया है और विरोधी शक्तियों को पीछे हटने पर मजबूर किया है। उन्होंने अपने बयान में धार्मिक और मनोबल से जुड़े पहलुओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि "अल्लाह की मदद से" ईरान ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया है। उनके अनुसार, वर्तमान घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि विरोधी देश अब अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हैं और इस संघर्ष से बाहर निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं—एक ऐसा संघर्ष, जिसकी शुरुआत उन्होंने खुद की थी। जनरल अब्दुल्लाही ने आगे कहा कि अमेरिकी नेतृत्व अब जमीनी हकीकत को समझने लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने लक्ष्यों में असफल रहने और स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने के बाद अमेरिका अब अन्य देशों का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक, यह स्थिति ईरान की जनता के लिए गर्व का विषय है, जिसने हर दबाव के बावजूद अपने संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने ईरानी जनता की बहादुरी, एकता और धैर्य की सराहना करते हुए कहा कि यही ताकत देश की सबसे बड़ी पूंजी है। उनके अनुसार, दुश्मनों की साजिशों और दबावों के बावजूद ईरान ने न केवल खुद को मजबूत बनाए रखा है, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है। अंत में, जनरल अब्दुल्लाही ने दोहराया कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं पूरी तैयारी और रणनीति के साथ हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और जनता की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस मिशन में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

ईरान की सत्ता में बड़ा बदलावः Masoud Pezeshkian ने Mohammad Bagher Zolghadr को बनाया राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया सचिव

लोकतंत्र की शान

ईरान की सत्ता संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने मंगलवार को Mohammad Bagher Zolghadr को देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (Supreme National Security Council) का नया सचिव नियुक्त किया। यह नियुक्ति इस्लामी गणराज्य के सर्वोच्च नेता Ali Khamenei की मंजूरी से की गई है, जिससे इस फैसले का राजनीतिक और रणनीतिक महत्व और बढ़ जाता है।

लारीजानी की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी-नव-नियुक्त सचिव Mohammad Bagher Zolghadr इस पद पर दिवंगत Ali Larijani का स्थान लेंगे। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब ईरान क्षेत्रीय तनाव, सुरक्षा चुनौतियों और अंतरराष्ट्रीय दबावों का सामना कर रहा है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि-वर्ष 1954 में फार्स प्रांत के Fasa शहर में जन्मे जुलक़द्र ने University of Tehran से अर्थशास्त्र में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने National Defense University से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की।

सैन्य और प्रशासनिक अनुभव- जुलक़द्र का करियर सैन्य और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक रहा है। ईरान-इराक युद्ध के दौरान सिपाहे पासदारान (IRGC) की संयुक्त समिति का नेतृत्व लगभग आठ वर्षों तक IRGC के डिप्टी कमांडर विभिन्न उच्च स्तरीय प्रशासनिक और रणनीतिक पदों पर कार्य

पहले भी संभाल चुके हैं अहम पद-सितंबर 2021 में, Ali Khamenei की सहमति से और Sadeq Amoli Larijani के निर्देश पर उन्हें Mohsen Rezaei की जगह हित संरक्षक परिषद (Expediency Discernment Council) का सचिव नियुक्त किया गया था। वे इस पद पर अब तक कार्यरत हैं।

रणनीतिक संकेत क्या हैं? विश्लेषकों के अनुसार, Mohammad Bagher Zolghadr की नियुक्ति केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह ईरान की सत्ता में सैन्य पृष्ठभूमि वाले नेताओं के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। IRGC से उनके गहरे संबंध और दशकों का अनुभव यह संकेत देता है कि आने वाले समय में ईरान की सुरक्षा और विदेश नीति और अधिक सख्त और रणनीतिक हो सकती है। यह नियुक्ति स्पष्ट करती है कि ईरान की सत्ता अब भी अनुभवी, पुराने और सुरक्षा तंत्र से जुड़े नेताओं के हाथों में केंद्रित है। ऐसे में यह फैसला न केवल आंतरिक राजनीति बल्कि क्षेत्रीय संतुलन पर भी असर डाल सकता है।

कुलदीप यादव पत्नी वंशिका के साथ बांके बिहारी मंदिर पहुंचे

पूजा-दर्शन करके 56 भोग अर्पित किए; शादी के बाद पहली बार वृंदावन आए

मथुरा (एजेंसी)। क्रिकेटर कुलदीप यादव ने पत्नी वंशिका के साथ वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए। वे मंगलवार शाम साढ़े 7 बजे मंदिर पहुंचे थे। दोनों ने देहरी (चौखट) पर इत्र लगाकर सेवा की। भगवान को 56 भोग अर्पित किए। शादी के बाद दोनों

पहली बार मथुरा पहुंचे थे।

कुलदीप इतनी गुपचुप तरीके से वृंदावन पहुंचे कि किसी को इसकी भनक तक नहीं हुई। फोटो-वीडियो सामने आने के बाद बुधवार सुबह लोगों को इसकी जानकारी हुई। दोनों करीब 25 मिनट तक मंदिर में रहे। इस दौरान मंदिर के गार्ड उन्हें घेरकर खड़े रहे। मंदिर के सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी ने बताया कि कुलदीप के परिवार ने उनके आने की जानकारी दी थी। भीड़भाड़ से बचने के लिए इसे गोपनीय रखने को कहा था। मंदिर पहुंचने पर मैंने और नितिन सांवरिया ने पूजा-अर्चना कराई। इत्र देकर चौखट की पूजा करवाई। भगवान की प्रसादी माला भेंट की। करीब एक घंटे वृंदावन में रहने के बाद दोनों दिल्ली रवाना हो गए। गर्भ गृह के पास चंदन कोठरी पर पहुंचे कुलदीप और वंशिका को सेवायत लवेश गोस्वामी ने भगवान की प्रसादी माला पहनाई। पूजा के बाद पुजारी ने प्रसाद के रूप में कुलदीप को वॉल हैंगिंग और वंशिका को मोर पंनख लगी बांसुरी भेंट की।

14 मार्च को मसूरी में हुई थी शादी

भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ 14 मार्च को मसूरी में शादी की थी। शादी में क्रिकेटर रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी पहुंचे थे। 17 मार्च को लखनऊ के होटल सेंट्रम में रिसेप्शन पार्टी हुई थी। सीएम योगी और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कुलदीप-वंशिका को आशीर्वाद दिया था।

केकेआर ने रसेल की जर्सी नंबर 12 रिटायर की

● आईपीएल में 11 साल टीम का हिस्सा रहे, 2 बार खिताब जिताया

कोलकाता (एजेंसी)। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने पूर्व ऑलराउंडर आंद्रे रसेल के सम्मान में उनकी जर्सी नंबर 12 को रिटायर कर दिया है। रसेल 2014 से 2025 तक टीम का हिस्सा रहे, सिर्फ 2017 सीजन को छोड़कर। पिछले साल नवंबर में उन्होंने आईपीएल से संन्यास लिया और अब टीम के पावर कोच की भूमिका निभा रहे हैं।

- **केकेआर के लिए खेले 133 मैच, 11 सीजन तक रहे पिलर-** आंद्रे रसेल का आईपीएल करियर मुख्य रूप से कोलकाता नाइट राइडर्स के इर्द-गिर्द ही रहा। उन्होंने अपने कुल 140 आईपीएल मैचों में से 133 मैच सिर्फ चयक्र के लिए खेले। वे 11 सीजन तक टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने रहे। रसेल ने न केवल अपनी बल्लेबाजी से, बल्कि अपनी डेथ ओवर गेंदबाजी से भी टीम को कई मुश्किल मैचों में जीत दिलाई।
- **2014 और 2024 की खिताबी जीत का रहे हिस्सा-** रसेल दो बार केकेआर की खिताबी जीत (2014 और 2024) का हिस्सा रहे। 2014 में उन्होंने सिर्फ 2 मैच खेले थे, लेकिन 2024 में टीम को चैंपियन बनाने में उनकी भूमिका सबसे बड़ी रही। उस सीजन में रसेल ने 15 मैचों में 185 के स्ट्राइक रेट से 222 रन बनाए और 19 विकेट भी झटके। गेंदबाजी में उनका औसत 15.52 का रहा, जो किसी भी ऑलराउंडर के लिए बेहतरीन आंकड़ा है।
- **कोचिंग पर बोले रसेल- खिलाड़ियों को वापस देने का समय है-** कोच की नई भूमिका को लेकर रसेल ने कहा,मुझे नहीं लगता कि कोच बनने से मेरी मानसिकता में कोई बदलाव आया है। यह उन खिलाड़ियों को कुछ वापस देने जैसा है जिनके साथ और जिनके खिलाफ मैं सालों तक खेला हूं। मुझे वापस आकर इन लड़कों की मदद करने में बहुत अच्छा लग रहा है।

ग्लोबल नाइट राइडर्स फैमिली का भी रहे चेहरा

रसेल का नाता सिर्फ आईपीएल वाली केकेआर से ही नहीं रहा, बल्कि वे नाइट राइडर्स की अन्य फ्रेंचाइजी के लिए भी खेलते रहे हैं। वे आईएलटी 20 में 'अबू धाबी नाइट राइडर्स' और सीपीएल में त्रिनबागो नाइट राइडर्स का भी हिस्सा रहे। इन दोनों ही टीमों के लिए उन्होंने 4-4 सीजन खेले हैं। इसके अलावा 2014-15 के चैंपियंस लीग टी-20 में भी उन्होंने चयक्रको फाइनल तक पहुंचाने में मदद की थी।

एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट

भारतीय तीरंदाजों ने जीते 2 ब्रोंज मेडल

थाईलैंड (एजेंसी)। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में चल रहे एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट (स्टेज-1) के दूसरे दिन भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने बुधवार को दो ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। इसके साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने मेंस रिकर्व और विमेंस कंपाउंड टीम इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है।

विमेंस कंपाउंड टीम- थाईलैंड को हराकर फाइनल में पहुंची- महिला कंपाउंड टीम ने सेमीफाइनल में थाईलैंड को 229-226 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। चिकिता तनिपार्थी, राज कौर और तेजल साल्वे की टीम अब खिताबी मुकाबले में तीसरे नंबर की सीड कजाकिस्तान से भिड़ेगी। पिछले साल टीम ने ब्रॉन्ज जीता था।

मेंस रिकर्व और विमेंस कंपाउंड टीम फाइनल में पहुंची; कजाकिस्तान से होगा मुकाबला

मेंस कंपाउंड टीम सेमीफाइनल में हारी- पुरुष कंपाउंड टीम को सेमीफाइनल में वियतनाम से 233-234 से हार का सामना करना पड़ा। टीम के पास बढ़त थी, लेकिन आखिरी पलों में मुकाबला हाथ से निकल गया। हालांकि टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में भूटान को 234-232 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। रजत चौहान, ऋषभ यादव और उदय कंबोज की अनुभवी टीम अपना खिताब डिफेंड करने में नाकाम रही। सेमीफाइनल में वियतनाम के खिलाफ एक समय भारतीय टीम 5 पॉइंट की बढ़त पर थी, लेकिन दूसरे और तीसरे एंड में वियतनाम ने परफेक्ट 60 का स्कोर कर वापसी की और भारत को 234-233 से हरा दिया।

मेंस रिकर्व टीम- मलेशिया को 5-1 से दी शिकस्त

पुरुष रिकर्व टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। देवांग गुप्ता, सुखचैन सिंह और जुयेल सरकार की टीम ने बिना कोई सेट गंवाए जीत दर्ज की और अब फाइनल में कजाकिस्तान से मुकाबला होगा। पहले सेट को भारत ने 53-50 और दूसरे को 53-52 से जीता। तीसरे सेट में मुकाबला 56-56 की बराबरी पर रहा, जो भारत को फाइनल में पहुंचाने के लिए काफी था। वहीं, महिला रिकर्व टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। रूमा बिस्वास, कीर्ति और रिधि फोर की टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।

बेन डकेट ने आईपीएल से नाम वापस लिया

● 2 साल के बैन का खतरा, सीएसके ने एलिस की जगह जॉनसन को किया शामिल

लंदन (एजेंसी)। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने आईपीएल 2026 से नाम वापस ले लिया है। खराब फॉर्म के बीच अपने टेस्ट करियर पर ध्यान देने के लिए उन्होंने यह फैसला लिया। हालांकि, आखिरी समय पर हटने के कारण उन्हें आईपीएल से दो साल के बैन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले साल फ्रेंचाइजियों ने ऐसे विदेशी खिलाड़ियों पर सख्ती करने का फैसला किया था।

वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को टीम में शामिल किया है। उन्हें चोटिल नाथन एलिस की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर 1.5 करोड़ रुपये की बेस प्राइस पर साइन किया गया है। एलिस

पुरानी हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।

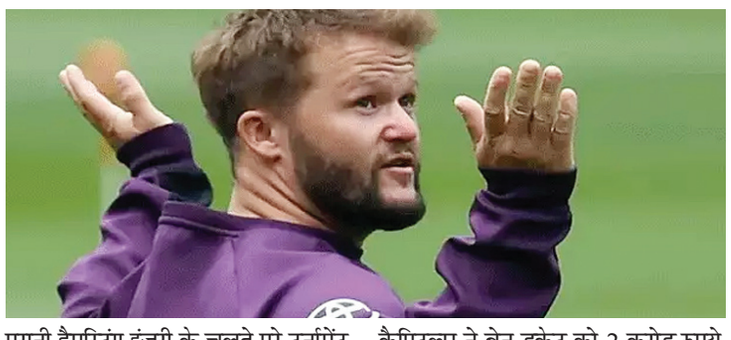

डीसी ने 2 करोड़ में खरीदा था, पथुम निसांका से मिल रही थी चुनौती- दिसंबर में हुए ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने बेन डकेट को 2 करोड़ रुपये में खरीदा था। डकेट पहली बार आईपीएल खेलने वाले थे, लेकिन टीम में विदेशी खिलाड़ी के स्लॉट के लिए उन्हें श्रीलंका के पथुम निसांका से कड़ी टक्कर मिल रही थी। प्लेइंग इलेवन में जगह पक्की न होने और फॉर्म के संकट को देखते हुए उन्होंने भारत आने के बजाय नॉटिंघमशायर के लिए काउंटी चैंपियनशिप खेलने का फैसला किया है।

डकेट बोले- दिल्ली से माफी मांगता हूं, यह करियर के लिए जरूरी था- 31 साल के डकेट ने 'द टेलीग्राफ' से बातचीत में कहा, यह बहुत कठिन फैसला था और मैं दिल्ली कैपिटल्स के सभी लोगों से माफी मांगता हूं। जब मुझे ऑक्शन में चुना गया था, तब मैं बहुत उत्साहित था। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, लेकिन मैंने अपने करियर के बारे में बहुत सोचा और मुझे लगा कि अभी यही सही फैसला है।

जॉनसन के लिए पिछला साल रहा था मुश्किल

जॉनसन 1.5 करोड़ रुपये में सीएसके से जुड़े हैं। 30 साल के इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने अब तक 5 वनडे और 8 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इसके अलावा वह 71 टी20 मुकाबलों का अनुभव भी रखते हैं।

जॉनसन पहले भी आईपीएल का हिस्सा रह चुके हैं। वह 2024 में गुजरात टाइटंस और 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले थे। 2024 सीजन में उन्होंने 5 मैचों में 4 विकेट लिए थे, जबकि 2025 में 4 मैचों में सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके। हालांकि, पिछले आईपीएल के बाद उन्हें बैक इंजरी हो गई थी, जिसके कारण वह बिग बैश लीग और 2026 टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर रहे। वहीं, पिछले साल आईपीएल के मिनी ऑक्शन में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था।

कर्ज संकट से निपटने को अनिल अंबानी का बड़ा प्लान, एसीबीआई समेत 2 बैंकों को लिखा लेटर

नईदिल्ली, एजेंसी। रिलायंस ग्रुप के मुखिया अनिल अंबानी कर्ज के जाल से बाहर निकलने के हर प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने समूह के बकाया देनदारियों के समाधान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सामने औपचारिक पहल की है। उन्होंने हालिया कानूनी उदाहरणों और अपने पिछले री-पेमेंट रिकॉर्ड का हवाला देते हुए एक स्ट्रक्चरल रिजॉल्यूशन प्रोसेस शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में अनिल अंबानी ने पत्र के जरिए भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी-सीईओ देबदत्ता चंद से संपर्क किया है। इन पत्रों में अनिल अंबानी ने एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व में एक लेंडर्स कमेटी गठित करने का अनुरोध किया है। इस कमेटी का उद्देश्य समूह की वास्तविक और कानूनी रूप से बकाया देनदारियों को स्पष्ट करना और एक समयबद्ध री-पेमेंट तैयार करना होगा।

रेलवे सेक्टर में बड़ा बदलाव, सरकार कर रही तैयारी

नईदिल्ली, एजेंसी। रेलवे सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार दो प्रमुख पीएसयू रेल विकास निगम लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल को मर्ज करने की तैयारी में है। इस फैसले का मकसद एक मजबूत और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर तैयार करना है, जो देश और विदेश में बड़े प्रोजेक्ट्स संभाल सके। बता दें इस खबर के बाद मंगलवार को दोनों कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। इरकॉन का शेयर करीब 2.9 प्रतिशत चढ़कर 119 पर बंद हुआ, जबकि 3.3 प्रतिशत बढ़कर 258 पर पहुंच गया। आज बुधवार को भी निवेशकों की नजर इन दोनों रेलवे स्टॉक्स पर रहेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अभी दोनों कंपनियां कई प्रोजेक्ट्स में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं। मर्जर के बाद यह कंपटिशन खत्म होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इससे मैनपावर, टेक्निकल क्षमता और फाइनेंशियल ताकत एक जगह आएगी, जिससे नई कंपनी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आसानी से बोली लगा सकेगी।

मर्जर के बाद बनने वाली नई कंपनी का संयुक्त ऑर्डर बुक 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान है। यह इसे देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों में शामिल कर सकता है। फिलहाल का मार्केट कैप करीब 53,877 करोड़ और का 11,159 करोड़ है।

100 डॉलर के नीचे आया कच्चा तेल

नईदिल्ली, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं, जबकि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। आज कच्चा तेल 100 डॉलर के नीचे आ गया है। ब्रेंट क्रूड 98.31 और 87.65 डॉलर प्रति बैरल पर थे। पेट्रोल-डीजल के उपभोक्ताओं के लिए राहत है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बढ़ाए हैं। आज 25 मार्च की सुबह छह बजे जारी रेट के मुताबिक दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंपों पर सामान्य पेट्रोल की रिटेल कीमत 94.77 और डीजल 87.67 रुपये लीटर है। जबकि, 95 पेट्रोल 101.89 और क्तत्र डीजल 91.49 रुपये प्रति लीटर है। शिमला में सामन्य पेट्रोल 95.05 रुपये और डीजल 87.13 रुपये प्रति लीटर है। 95 पेट्रोल की कीमत यहां 103.66 रुपये लीटर है।

भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल कहां मिलता है: बता दें भारत में सबसे सस्ता तेल पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल 82.46 प्रति लीटर है तो डीजल 78.05 प्रति लीटर। दूसरी ओर अन्य शहरों की बात करें तो सिलवासा, दादरा और नगर हवेली में पेट्रोल 92.37 प्रति लीटर है। हरिद्वार, उत्तराखंड में

पेट्रोल 92.78 लीटर है वहीं, रुद्रपुर में 92.94 प्रति लीटर। ईटानगर में पेट्रोल 90.87 प्रति लीटर है जबकि, डीजल 80.38 प्रति लीटर।

आज पश्चिम बंगाल के शहरों में पेट्रोल के दाम: अलीपुर में पेट्रोल 104.99 प्रति लीटर, बहरामपुर में 106.12, बांकुड़ा में 105.19, बारासात में 105.24, वर्धमान में 105.33, कूचबिहार में 106.14, हुगली में 105.52, हावड़ा में 104.99, कोलकाता में 104.99, कृष्णानगर में 106.07, मेदिनीपुर में 105.37, पुरुलिया में 106.05 प्रति लीटर है।

युद्ध में नरमी के संकेत, बाजार को मिला सहारा: मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष अब चौथे सप्ताह में पहुंच चुका है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है और संभावित हमलों को फिलहाल टाल दिया गया है। हालांकि, ईरान ने आधिकारिक तौर पर बातचीत से इनकार किया है, लेकिन रिपोर्ट्स में दोनों देशों के बीच किसी स्तर पर संपर्क होने की बात कही जा रही है। इससे बाजार में थोड़ी राहत आई है।

कच्चे तेल में जबरदस्त उतार-चढ़ाव: युद्ध के कारण हॉर्मुज जलडमरूमध्य से तेल सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमत फरवरी के अंत में करीब 70 से बढ़कर 108 प्रति बैरल तक पहुंच गई। हालांकि, तनाव कम होने के संकेत मिलने के बाद यह 100 से नीचे फिसलकर फिर 98 के आसपास पहुंच गया। इस तरह वैश्विक बाजार में भारी अस्थिरता बनी हुई है।

आम ग्राहकों को राहत, लेकिन इंडस्ट्रियल फ्यूल महंगा= जहां आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इंडस्ट्रियल डीजल और प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत में 21.92 प्रति लीटर (करीब 25 प्रतिशत) की भारी बढ़ोतरी की गई है, जबकि प्रीमियम पेट्रोल 2 प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसका असर उद्योगों और परिवहन लागत पर पड़ सकता है।

अडानी की कंपनी में मॉर्गन स्टैनली ने बेची हिस्सेदारी, करीब 7 लाख शेयर की डील

नईदिल्ली, एजेंसी। गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी में कुछ ब्लॉक डील हुई है। इसके तहत फ्रेंच मल्टीनेशनल बैंक खरीदार था जबकि मॉर्गन स्टैनली बेचने वाला था। बीएनपी ने अपनी सहयोगी कंपनी के ज़रिए कंपनी के 6.9 लाख शेयर खरीदे। जानकारी के मुताबिक इस डील की कीमत 56 करोड़ रुपये थी। बता दें कि ये शेयर 808.3 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे गए, जो सोमवार की क्लोजिंग कीमत 816.45 रुपये से 1 प्रतिशत कम थी। वहीं, मॉर्गन स्टैनली ने अपनी इन्वेस्टमेंट विंग मॉर्गन स्टैनली एशिया (सिंगापुर) के ज़रिए उतने ही शेयर बेचे। इस बीच, बीएसई पर अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 2.76 प्रतिशत बढ़कर 839.30 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। इस शेयर ने एक साल की अवधि में 12 प्रतिशत की गिरावट देखी है। इसके विपरीत क्रमशः 2 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की गिरावट आई है।

बता दें कि फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी टोटलएनर्जीज ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में अपनी 1.7 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है। कंपनी ने बीती तिमाही और वर्ष 2025 के अपने वित्तीय नतीजों पर जारी बयान में बताया था कि उसने अक्टूबर-दिसंबर, 2025 के दौरान परिसंपत्तियों की बिक्री से 2.08 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए। टोटलएनर्जीज के मुताबिक, इन विनिवेश में नाइजीरिया के बोंगा क्षेत्र में गैर-संचालित हिस्सेदारी की बिक्री, मलेशिया के ब्लॉक एसके408 में आंशिक हिस्सेदारी की बिक्री, अमेरिका और यूनान में अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री तथा अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.7 प्रतिशत

हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है। टोटलएनर्जीज ने जनवरी, 2021 में अडानी ग्रीन में अल्पांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था।चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अडानी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा लगभग 98.94 प्रतिशत घटकर पांच करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से खर्च बढ़ने के कारण कंपनी का लाभ घटा है। पिछले वर्ष की समान तिमाही (दिसंबर 2024) में उसने 474 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया था। तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 2,961 करोड़ रुपये हो गया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेल:- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)